twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | गुरूवार, 17 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 241, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

पीएम धन-धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी

एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की भी मंजूरी

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह एलान किया है। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावे कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है।

क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना?

मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसमें 100 जिले शामिल होंगे। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने मदद देगा।

भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में होगा सुधार

केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी साझा करते हुए, सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना से फसल के बाद भंडारण में वृद्धि होगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

एनएलसी इंडिया एनआईआरएल में कर सकेगा 7000 करोड़ रुपये का निवेश

सरकार ने बुधवार को एनएलसी इंडिया को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एनआईआरएल में 7,000 करोड़ रुपये निवेश करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से लिया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिदेशों से विशेष छूट देने को मंजूरी दे दी है।

शुभांशु की पृथ्वी पर वापसी से जुड़ा प्रस्ताव भी पारित

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर भी एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह स्पेस की दिशा में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, "आईएसएस (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर

मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्तरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल, देश के साथ मिलकर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया।"

नवीकरणीय ऊर्जा में 20000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी को 2032 तक 60 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की अनुमति दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में लिए गए निर्णय के बारे में बताया। एनटीपीसी के लिए पहले स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपये थी। सरकार की ओर से बताया गया है कि एनटीपीसी और एनजीईएल को दी गई अनुमति देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद करेगी। बयान में कहा गया है कि यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने में निवेश सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इस रणनीतिक निर्णय से एनएलसीआईएल को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने में मदद मिलेगी। इसके तहत एनआईआरएल विभिन्न परियोजनाओं में सीधे या संयुक्त उद्यम का गठन कर निवेश कर सकेगी। इसके लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

श्री हरिमंदिर साहिब को उड़ाने की धमकी

अमृतसर/एजेंसी

अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल आया है। लगातार तीसरे दिन ऐसी धमकी आई है। यह ईमेल एसजीपीसी के प्रबंधकों को भेजा गया है। जिसके बाद श्री हरिमंदिर साहिब परिसर और उसके आसपास पुलिस की ओर से सुरक्षा को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक एसजीपीसी को बुधवार को फिर से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि आसपास की पाइपों में आरडीएक्स भर दिया गया है और इसी के साथ धमाके किए जाएंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साइबर सेल की ओर से ईमेल की जांच की जा रही है। जल्द ही इन शरारती तत्वों को दबोच लिया जाएगा। श्री हरिमंदिर साहिब को आने जाने वाले हर एक रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों के सामान आदि की भी जांच की जा रही है। धमकी के बाद श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास पंजाब पुलिस के साथ-साथ बीएसएफ को भी तैनात किया गया। वहीं इसके अलावा पूरे इलाके में डॉग और बम स्क्वायड भी तैनात कर दिए गए है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उनकी साइबर टीम इस काम में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहरा कड़ा कर दिया है। किसी भी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने मच्छरों का लार्वा तीसरी बार मिलने पर चालान काटने के निर्देश दिए

नई दिल्ली/एजेंसी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आलाधिकारियों मच्छरों का लार्वा मिलने पर दो बार चेतावनी देने के बाद तीसरी बार चालान काटने के निर्देश दिए हैं।

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' फिलहाल नहीं होगी रिलीज, कोर्ट को केंद्र के फैसले का इंतजार

नई दिल्ली/एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीजिंग पर सुनवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म को रिलीज न करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी। टेलर कन्हैया लाल के जीवन पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' शुरू से ही विवादों में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिल्म के लिए रिव्यू पैनल का गठनकिया है।

दोपहर 2:30 बजे पैनल की बैठक

होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को जल्द से जल्द मामले पर सुझाव देने का आदेश दिया है।

आरोपियों ने जताई आपत्ति

कन्हैया लाल के मर्डर के आरोपी मोहम्मद जावेद ने भी फिल्म की रिलीजिंग पर आपत्ति जताई है। कमेटी को इसपर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स और कन्हैया लाल के बेटे को पुलिस से मदद लेने के लिए कहा है। अगर उनकी सुरक्षा को खतरा है तो वो पुलिस से सिक्योरिटी ले सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' राजस्थान के टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। 12 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और मोहम्मज गौस ने धारदार हथियार से कन्हैया की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने वीडियो रिलीज करते हुए हत्या की वजह भी बताई थी।

विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी: सीडीएस

नई दिल्ली/एजेंसी

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा विदेश से इम्पोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी C-UAS (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है।

हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके।

सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वअश (अनमैंड एरियल व्हीकल) और C-UAS (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) की प्रदर्शनी में कहीं। CDS बोले- सेना ने ड्रोन्स का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा- मुझे लगता है कि ड्रोन्स इवॉल्यूशनरी (विकासवादी) हैं और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है। जैसे-जैसे उनकी तैनाती और दायरा बढ़ा, सेना ने क्रांतिकारी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया।

अकबर 'क्रूर लेकिन सहिष्णु', औरंगजेब 'कट्टर धार्मिक': एनसीईआरटी

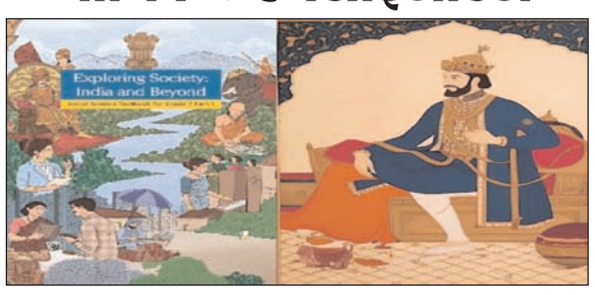

एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा; कक्षा 8 के सिलेबस में शामिल हुआ

नई दिल्ली/एजेंसी

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से स्कूलों में शुरू की जाने वाली आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल काल की नए सिरे से समीक्षा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि अकबर क्रूर होते हुए भी सहिष्णु था, जबकि औरंगजेब एक कठोर शासक था। अकबर का शासनकाल 'क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण' था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने 'गैर-इस्लामी' प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर-मुसलमानों पर फिर से कर लगाए। प्रमुख मुगल सम्राटों के चित्रण में यह पुस्तक एक बदलाव का प्रतीक है जिसमें विजय, धार्मिक निर्णयों, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता का विस्तृत विवरण दिया गया है।

किसी को नहीं जिम्मेदार ठहराना गलत

एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तक में इस तरह के विवरणों को शामिल किए जाने पर कहा, 'इन घटनाओं को न तो मिटाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है, लेकिन आज किसी को भी इनके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। क्रूर हिंसा, अपमानजनक कुशासन या सत्ता की गलत महत्वाकांक्षाओं के ऐतिहासिक मूल को समझना, अतीत को सुधारने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है जहां संभवतः इनका कोई स्थान नहीं होगा।'

2029 तक विपक्ष में नहीं जाएंगे: फडणवीस

पुणे/एजेंसी

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2029 तक भाजपा या उनका गठबंधन विपक्ष में जाने वाला नहीं है। उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे को इशारों में सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर भी दिया। यह बयान उस वक्त आया है जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भाजपा की यह रणनीति बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना (उद्धव

गुट) की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास भी हो सकती है। विधान परिषद सत्र के दौरान बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम 2029 तक हमारे विपक्ष में जाने की कोई संभावना नहीं है। यह बयान राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। भरी विधान परिषद में उन्होंने कि उद्धव जी चाहें तो इस तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम 2029 तक तो हम विपक्ष में नहीं आएंगे। ऐसे में अब एक और संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह विचार एक अलग तरीके से किया जा सकता है, जिससे यह बयान और ज्यादा सियासी मायनों से भर गया है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब मुंबई की बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछली बार बीएमसी में शिवसेना और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी। बीएमसी फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के नियंत्रण में है। भाजपा चाहती है कि इस बार वह बीएमसी पर कब्जा करे और इसके लिए वह सभी राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गई है।

10 लाख नागरिकों को मिलेगा नि:शुल्क एआई प्रशिक्षण

नई दिल्ली/एजेंसी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने घोषणा की है कि 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित डिजिटल इंडिया उत्सव के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएससी नेटवर्क ने देश के लगभग 90 प्रतिशत गांवों तक पहुंच बनाई है। मंत्री ने ग्रामीण उद्यमियों की प्रेरक कहानियों का उल्लेख किया, जिन्होंने डिजिटल कौशल हासिल कर अपने समुदायों को सशक्त बनाया है।

पहलगाम के आतंकवादियों का सफाया जल्द होगा: मनोज सिन्हा

नई दिल्ली/एजेंसी

जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्दी ही देश को पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का सफाया होने की खबर मिलेगी। मनोज सिन्हा ने बुधवार को यहां गांधी स्मृति एवं दर्शन में जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना विषय पर एक व्याख्यान में कहा कि जम्मू एवं कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35ए हटने के बाद भारत के साथ वहां के लोगों का एकीकरण पूरा हो गया है। कश्मीर घाटी के लोगों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। उप राज्यपाल ने कहा कि पहलगाम में हमले में शामिल

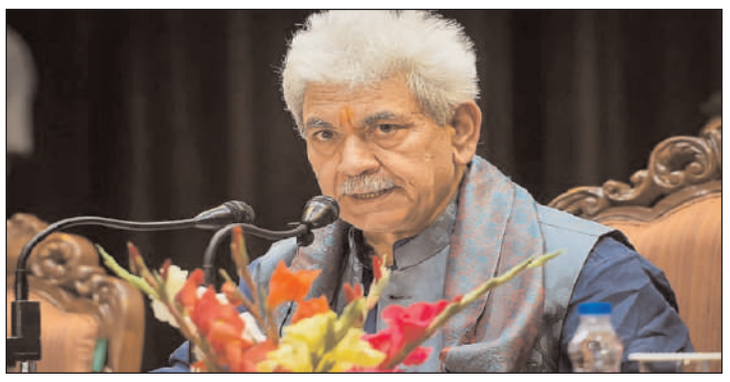

आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है और उनकी भौगोलिक स्थिति का भी पता चल चुका है। बहुत जल्दी देश को उनके सफाया होने की खबर मिलेगी। सिन्हा ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बापू के सिद्धांत पर शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल की पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस स्वतः स्फूर्त ढंग से जनता में आतंकवाद-विरोधी लहर दिखाई दी वो बीते 50 साल में कभी नहीं दिखी थी। लोगों ने पड़ोसी देश के एजेंडे को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिली है। पांच साल में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और निर्यात दोगुने से अधिक हो गये हैं। जम्मू कश्मीर बैंक पांच साल पहले 1300 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा था और आज यह बैंक 1700 करोड़ रुपये से अधिक के मुनाफे में है। यहां निष्पक्ष चुनाव हुए और उनकी पसंद की सरकार बनी।

मनोज सिन्हा ने कहा कि पांच साल में कश्मीर में 5000 से अधिक नये होटल बने हैं। 15 हजार से ज्यादा नयी गाड़ियां खरीदी गई हैं। बीते साल दो करोड़ 38 लाख पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में समृद्धि आयी और उनमें यह समझ बनी कि उनका भविष्य भारत में ही उज्ज्वल है। इस प्रकार से पाकिस्तान के एजेंडे के लिए समर्थन समाप्त हो गया।

उप राज्यपाल ने कहा कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को जो किया, उसके पीछे उनका मकसद था कि देश में धार्मिक वैमनस्य बढ़े। देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी लोगों पर हमले हों और कश्मीर के लोग फिर से पाकिस्तानी एजेंडा में फंस जाए।

डीआरडीओ ने नौसेना को सौंपी छह स्वदेशी डिजाइन और विकसित उत्पाद प्रणालियां

एजेंसी

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय नौसेना को 6 रणनीतिक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां सौंपी हैं, जिससे समुद्री सेना की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया पहला भारत में निर्मित किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फ़ुट प्रोस्थेसिस का तेलंगाना में अनावरण किया गया। आयातित कृत्रिम पैर की लागत लगभग दो लाख रुपये है, जबकि भारत में विकसित इस उत्पाद की कीमत 20? हजार रुपये से भी कम होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव और डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी. कामथ ने रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में नौसेना मुख्यालय के रियर एडमिरल श्रीराम अमूर एसीएनएस (एसएसपी) को ये उत्पाद सौंपे। भारतीय नौसेना को सौंपे गए छह रणनीतिक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उत्पादों में गामा विकिरण हवाई निगरानी प्रणाली (ग्रास), पर्यावरण निगरानी वाहन (ईएसवी), वाहन रेडियोलॉजिकल संदूषण निगरानी प्रणाली (वीआरसीएमएस), जल के भीतर गामा विकिरण निगरानी प्रणाली (यूजीआरएमएस), डर्ट एक्सट्रैक्टर और क्रॉस संदूषण मॉनिटर (डेकॉम) और ऑर्गन रेडियोधर्मिता पहचान प्रणाली (ओआरडीएस) हैं। मानव रहित गामा विकिरण हवाई निगरानी

प्रणाली पर्यावरणीय निरंतर निरीक्षण और गंभीर दुर्घटनाओं में आपातकालीन निरीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गामा विकिरण डिटेक्टर एक विकिरण निगरानी प्रणाली का दिल बनाता है, इसलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में इस तरह के डिटेक्टरों की तैनाती महत्वपूर्ण है। पर्यावरण निगरानी वाहन विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों को मापने और निगरानी करने के लिए सेंसर और उपकरणों से सुसज्जित होता है। यह वाहन वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण स्तर जैसे विभिन्न कारकों की निगरानी करके डेटा को एकत्र करके विश्लेषण के लिए भेजता है। नौसेना को सौंपी गई वाहन रेडियोलॉजिकल संदूषण निगरानी प्रणाली वाहनों में रेडियोधर्मी संदूषण का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदूषण को फैलने से रोका जा सके। ये प्रणालियां आमतौर पर वाहनों के माध्यम से गुजरने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने के लिए डिटेक्टरों का उपयोग करके खतरे की स्थिति में अलर्ट जारी करती हैं। गामा विकिरण निगरानी प्रणाली पानी के अंदर गामा विकिरण के स्तर को मापने के लिए एक विशेष प्रणाली है। यह प्रणाली समुद्र, झीलों या अन्य जल निकायों में रेडियोधर्मी प्रदूषण या असामान्य विकिरण स्तरों का पता लगाने में मदद करती है। इस प्रणाली में आमतौर पर एक या एक से अधिक गामा किरण डिटेक्टर होते हैं, जो पानी के भीतर स्थापित किए जाते हैं।

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में समय रैना समेत पांच लोगों को अगली सुनवाई में होना होगा पेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

एजेंसी

नई दिल्ली । दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल सहित पांच लोगों को तलब किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में भी इन सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। हालांकि, कॉमेडियन सोनाली ठक्कर को व्यक्तिगत समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बताया कि मुंबई पुलिस और सभी आरोपितों ने अपने-अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। फिलहाल कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने समय रैना समेत पांच कॉमेडियन को चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि समय रैना, विपुल गोयल, निशांत जगदीश तंवर, सोनाली ठक्कर और बलराज परमजीत सिंह घई को कोर्ट ने 5 मई को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था।

राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत

लखनऊ । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी। यह मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को ही कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने के आदेश के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया। इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कोर्ट की ओर से तलब किए जाने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। न्यायालय ने जमानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। कोर्ट ने भी माना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी।

जयशंकर ने की चीनी राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति से कराया अवगत

एजेंसी

बीजिंग। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिष्टाचार मंगलवार को भेंट की और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।डॉ जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शुभकामना संदेश प्रेषित किये। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के बारे में अवगत कराया। विदेश मंत्री ने एक्स पर इससे जुड़ी तस्वीर भी साझा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति से अवगत कराया। इस संबंध में वे दोनों देशों नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। विदेश मंत्री चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने यहां की यात्रा पर हैं। कल उन्होंने अपने चीनी समकक्ष के साथ वार्ता की थी। इसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हालिया सकारात्मक प्रगति को बनाए रखने और सीमावर्ती मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि यह आवश्यक है कि हम अपने संबंधों के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएँ और रणनीतिक संवाद को नियमित करें।

यमन में हत्या के आरोप में सजा काट रही नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टली

16 जुलाई को दी जानी थी फांसी

एजेंसी

नई दिल्ली। यमन में हत्या के आरोप में सजा काट रही नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई, 2025 को होने वाली फांसी की सजा को स्थगित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार, जो मामले की शुरुआत से ही इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है, ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुंचने के लिए और अधिक समय मांगने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इसमें शामिल संवेदनशीलताओं के बावजूद, भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक के कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में हैं, जिससे इस स्थगन को सुनिश्चित किया जा सका निमिषा 2008 से

यमन में रह रही है। निमिषा को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। इससे पहले, निमिषा के परिजनों ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर निमिषा की फांसी रोकने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप की भी मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निमिषा के परिजनों को हर संभव सहायता देने की दिशा में हम प्रयासरत हैं।यमन के अदालत के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि नर्स निमिषा प्रिया ने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी थी। यही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने एक अन्य नर्स की सहायता से उसके शव के टुकड़े करके टैंक में फेंक दिए थे। निमिषा प्रिया के परिजनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने हत्या नहीं की थी, बल्कि निमिषा ने कथित तौर पर अपना जब्त पासपोर्ट पाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। लेकिन, ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई।

राहुल के 'क्राइम कैपिटल' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सलाह- 'आंख-कान का कराएं इलाज'

एजेंसी

पटना । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उन्हें आंख और कान का सही चिकित्सक से इलाज कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न तो सही से दिखाई दे रहा है और न ही सुन पा रहे हैं। राय ने कहा कि राहुल गांधी को 1990 से 2005 की स्थिति भी याद करनी चाहिए, जब बिहार जंगलराज बन चुका था। आज की स्थिति देखकर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस दौर में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, व्यापारियों का अपहरण हो रहा था। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो आज कार्रवाई होती है। दुनिया कह रही है कि बिहार में विकास हो रहा है। राजद के नेता तेजस्वी यादव के अपराधी सम्राट और विजय होने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अब अपराधी जेल में रहते हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलती है। पहले अपराधी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवास में मिलते थे। वे अपराध करके आते थे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती थी। इस

तरह का माहौल बिहार ने देखा है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि 2020 में जब तेजस्वी यादव को ये भ्रम हो गया था कि वे सीएम बनने जा रहे थे, तब उनके समर्थकों ने सिर्फ दो दिनों में पटना से लेकर गांव तक क्या तांडव मचाया था? यह उनके चरित्र को बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को राहतः सुप्रीम कोर्ट में मान्यता रद्द करने की याचिका ली गई वापस

एजेंसी

नई दिल्ली । असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। याचिकाकर्ता ने पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका वापस ले ली है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि वह नई याचिका दाखिल कर सकता है।

यह याचिका शिवसेना (तेलंगाना विंग) के अध्यक्ष तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एआईएमआईएम संविधान में निहित सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी केवल एक विशेष समुदाय के हितों की बात करती है, जो कि भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि अगर मैं चुनाव आयोग के पास जाकर कहूं कि मैं वेदों और पुराणों को आधार बनाकर पार्टी बनाना चाहता हूं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर कैसे एआईएमआईएम को अल्पसंख्यक

वर्ग के धार्मिक विचारों पर आधारित पार्टी के तौर पर मान्यता दी गई? उन्होंने आगे कहा कि संविधान में सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के गठन का अधिकार दिया गया है, राजनीतिक पार्टी का नहीं। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देकर संविधान के सेक्युलर ढांचे का उल्लंघन किया है। इस पार्टी का एजेंडा ÷सांप्रदायिक और एकपक्षीय÷ है। पार्टी का एकमात्र मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय के पक्ष में काम करना है। याचिकाकर्ता का दावा था कि यह पार्टी देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ कार्य कर रही है। याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस जरूर ले लिया है, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि वे तथ्यों और कानून के आधार पर भविष्य में नई याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल याचिका का वापस लिया जाना एआईएमआईएम के लिए एक अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है।

फौजा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मान ने शोक व्यक्त किया

एजेंसी

जालंधर/नयी दिल्ली। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब के जालंधर जिले में मैराथन धावक फ़ौजा सिंह का उनके पैतृक गांव ब्यास के पास सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 114 वर्ष के थे। फौजा सिंह, जिन्हें प्यार से 'टर्बन्ड टॉरनेडो' कहा जाता था, इस वर्ष एक अप्रैल को 114 वर्ष के हुए थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक संदेश में कहा, 'फौजा सिंह जी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के अपने तरीके के कारण असाधारण थे। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। उनके निधन से बहुत दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक संदेश में कहा, 'प्रसिद्ध पंजाबी सिख धावक फौजा सिंह जी के देहांत की खबर सुनकर बेहद दुःख हुआ। अपनी लंबी दौड़ों के दम पर पूरी दुनिया में सिख टॉरनेडो' लिखी थी, ने सोशल मीडिया एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'मेरा पगड़ीधारी टॉरनेडो अब नहीं रहा। मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने परम श्रद्धेय स्व. फ़ौजा सिंह के निधन की

कौम का नाम रोशन करने वाले, विश्व के सबसे अधिक उम्र के धावक फौजा सिंह जी हमेशा हमारे दिलों और यादों में जीवित रहेंगे। परिवार और चाहने वालों के साथ दिल से संवेदना। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। वाहेगुरु वाहेगुरु'। लेखक खुशवंत सिंह, जिन्होंने उनकी जीवनी 'टर्बन्ड सूचना मिल रही है। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे उनके गाँव बियास में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मेरे प्रिय फ़ौजा, उनकी आत्मा को शांति मिले। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर शोक जताया है।

बिहार कैबिनेट में पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी देने सहित 30 प्रस्तावों पर मुहर

एजेंसी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य सहित कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पटना स्थित पुराने सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। इसके तहत अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देगी इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। बिहार सरकार वर्ष 2025 से 2030

के दौरान पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। इसके लिए कुल 12 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय 6000 रुपये देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कृतिका सिंह, डॉ कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉक्टर चंदना कुमारी और जमुई में तैनात डॉक्टर निमीषा रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इन सभी को लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पटना की ही तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है।

अभिनेता और फिल्म निर्माता धीरज कुमार का निधन

एजेंसी

मुंबई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार सुबह 79 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। धीरज के निधन की खबर से हिंदी सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशंसक और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि उनके परिवार और प्रोडक्शन टीम ने की गई थी।धीरज पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थे और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें एक दिन पहले ही निमोनिया की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। परिवार ने इस दौरान लोगों से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की थी और साथ ही आग्रह किया था कि इस मुश्किल समय में उनकी निजता का सम्मान किया जाए। जिंदगी और मौत की इस जंग में अंततः धीरज कुमार हार गए और उन्होंने अंतिम सांस ली। इस संबंध में अभी तक उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है।

मप्र के दरवाजे सभी के लिये खुले हैं, हर क्षेत्र में निवेशकों का स्वागत हैः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गरीब से गरीब आदमी को सम्पन्न बनाने का संकल्प है। बदलते दौर का भारत प्रधानमंत्री मोदी के गत 11 वर्ष के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का प्रमाण है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के संकल्प की पूर्ति के लिए उद्योग और अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में भारत के निरंतर सशक्त होने में पूरी तरह सहभागी है। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहनकारी नीतियों का लाभ देने के साथ ही नीतियों से हटकर भी अतिरिक्त सुविधाएं देने का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश सभी सेक्टर के निवेशकों का स्वागत कर रहा है। हम इसी उद्देश्य से दुबई आए हैं। मध्य प्रदेश के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार देर शाम दुबई में इन्वेस्ट इन मप्र बिजनेस- फोरम के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दुबई के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में पर्यटन,टेक्सटाइल और एमएसएमई सहित अन्य सेक्टर्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता यह है कि उद्यमी न करे धनसंग्रहित बल्कि उस धन को उद्यम में लगाकर अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं। इससे व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। व्यापार की यह समझ दुबई के उन उद्योगपतियों में है जो भारतीय हैं और इस देश के विकास में विशेष सहयोगी हैं। टेक्समास टेक्सटाइल क्षेत्र देखकर सुखद अनुभव हुआ है, यहां योजना पक्ष की श्रेष्ठता देखने को मिली है। यह मॉडल मध्यप्रदेश में भी लागू करने का प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब से गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिला पाएं, इसके लिए सरकार सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के जो लाभ हैं उनके बारे में मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। भारत के साथ दुबई के परस्पर प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध हैं। दुबई का इतिहास देखें तो 19वीं सदी में यह मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्ष 1950 से 1970 के मध्य तेल की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को बदल दिया। आज दुबई गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के कारण जाना जाता है।

लूटे गए मोबाइल को भेजते थे बांग्लादेश, छह गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी जिला के एंटी नारकोटिक्स स्क्वायड ने अंतरराज्जीय गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से कुल 27 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी, वारदात के समय पहने कपड़े और झपटमार की पत्नी के बैंक खाते के कागजात बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सलमान (37), शफी अहमद उर्फ टीपू (33), भूपेंद्र (34), गुलबहार (37), मोहम्मद रहमान शेख (35) और अमीरुल कयूस (36) के रूप में हुई है। दिल्ली-एनसीआर से लूटे गए मोबाइल फोन को बदमाश कूरियर के जरिए पश्चिम बंगाल भेज देते थे। बाद में गैंग के बाकी सदस्य उनको बांग्लादेश भेज देते थे। पुलिस ने गिरोह की गिरफ्तारी से फिलहाल मोबाइल लूटने के 9 मामले सुलझा लेने का दावा किया है। गुलबहार सलमान की पत्नी है। लूटे गए मोबाइल के पैसे गुलबहार के बैंक खाते में आते थे। पूर्वी जिला जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 25 जून को बदमाशों ने पटपड़गंज, मंडावली और प्रीत विहार इलाके में तीन मोबाइल फोन झपटे थे। वारदात में एक ही गिरोह का हाथ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस ने 400 सीसीटीवी कैमरों की खंगाले। जांच के बाद आरोपित की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

तुर्कमान गेट इलाके में घर से मिला युवक का शव

नई दिल्ली। मध्य जिला के कमला मार्केट स्थित तुर्कमान गेट इलाके में रविवार रात एक युवक की लाश मिली। स्थानीय लोगों ने घर से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर युवक की सड़ी-गली लाश बरामद हुई। जांच में मृतक की पहचान इमरान (34) के रूप में हुई है। क्राइम टीम और एफएसएल को मौके पर बुलाया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। बाद में शव को कब्जे में लेकर एलएनजेपी अस्पताल के शवगृह में भेज दिया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का पता चल पाएगा। पुलिस के मुताबिक इमरान परिवार के साथ मोमग्रान, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट इलाके में रहता था। इसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। इमरान एक बड़े मीडिया हाउस में प्रोमोशन की नौकरी करता था। तीन दिन पहले इसकी पत्नी पुरानी दिल्ली स्थित अपने मायके गई थी। इसके बाद से लोगों ने उसे नहीं देखा था। रविवार रात को पड़ोसियों ने इमरान के घर से तेज दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

कांग्रेस ने छात्रा आत्मदाह मामले में ओडिशा सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ओडिशा के बालासोर जिले में फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा के आत्मदाह मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को भाजपा शासित ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल बताया। लांबा ने कहा कि पीड़ित छात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की पदाधिकारी है। उसपर कॉलेज के बीएड विभाग के अध्यक्ष समीर कुमार साहू लगातार यौन उत्पीड़न के लिए दबाव बना रहे थे। साहू ने धमकी दी थी कि यदि छात्रा उनकी मांगें नहीं मानी, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रा ने 30 जून को इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष से की और 01 जुलाई को स्थानीय भाजपा सांसद, ओडिशा के मुख्यमंत्री और विभाग को सूचित किया। हालांकि, विभाग ने छात्रा को चेतावनी दी कि यदि वह आरोप साबित नहीं कर पाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लांबा ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी ने 10 दिनों तक साहू के बजाय छात्रा से ही सवाल किए, जिससे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई। न्याय की उम्मीद टूटने पर छात्रा 11 दिन बाद धरने पर बैठी और फिर कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली। 95 प्रतिशत जल चुकी छात्रा भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती है।

संसद के कामकाज में एआई का प्रवेश

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा के कामकाज में आर्टिफीशियल इन्टेलीजेंस(एआई) आधारित डिजीटलीकरण का अगला चरण लागू किया जाएगा, जिसमें दो नई भाषाओं में अनुवाद की सेवा और सांसदों की उपस्थिति डिजीटली दर्ज करना शामिल है। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने आज बताया कि इस सत्र से लोकसभा में सांसदों को हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के अलावा में सदन में उनके लिए आवंटित सीट पर मल्टीमीडिया माध्यम से बायोमेट्रिक ढंग से (अंगूठे या उंगली के निशान से) अथवा पिन नंबर दर्ज करके हाजिरी लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। आने वाले समय में रजिस्टर पर हस्ताक्षर की परंपरा को बंद करके केवल डिजीटल माध्यम से हाजिरी लगाने का प्रक्रिया अपनायी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि लोकसभा में इस समय 17 भाषाओं में अनुवाद की सेवा उपलब्ध है। सांसदों को सदन में जिस भाषा में बोलना होता है, उसके बारे में एक निश्चित अवधि पहले टेबल ऑफिस को नोटिस दिया जाता रहा है।

दिल्ली सरकार 'पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप' कार्यक्रम शुरू कर रही है : रेखा गुप्ता

40 युवाओं को हर महीने 50 हजार रुपये मिलेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रचार-प्रसार और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 'पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप' कार्यक्रम शुरू कर रही है। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 40 युवाओं को फेलोशिप के लिए चुना जाएगा और उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है, जो देश की आंतरिक क्षमताओं और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देती है और बाहरी सलाहकारों पर निर्भरता कम करती है। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगी जो सरकारी परियोजनाओं से सीधे जुड़कर दिल्ली

को एक जीवंत, समावेशी और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में योगदान देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी)) द्वारा चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं, शोधकर्ताओं और पर्यटन क्षेत्र में रुचि रखने वाले पेशेवरों को दिल्ली की समृद्ध विरासत से जोड़ना और पर्यटन के क्षेत्र में संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है। ये युवा विरासत भ्रमण, मार्गदर्शित पर्यटन यात्राएं, डिजिटल व प्रचार सामग्री निर्माण, पर्यटन प्रचार, कार्यक्रम प्रबंधन, दिल्ली हाट, गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस, पर्यटन सूचना केंद्रों का संचालन, फिल्म शूटिंग समन्वय और एमआईसीई बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां जैसी गतिविधियों में योगदान देंगे।

इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को हर महीने 50,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा और एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र भी मिलेगा। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले युवा आवेदक की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री या समकक्ष होगी। वैसे पर्यटन में डिग्री/स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को पर्यटन या संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का औपचारिक अनुभव होना चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता तथा डिजिटल कौशल आवश्यक हैं।

पुलिस ने नकली नोटों से 40 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण जिला की स्पेशल स्टाफ ने एक बड़े ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया किया है। आरोपित लोगों को नकदी के बदले बैंक में जमा पैसे एक्सचेंज करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान निखिल, प्रिंसपाल, परवेज और असगर खान उर्फ अख्तर खान उर्फ बंटी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.25 करोड़ रुपये की डमी करेंसी (जिन पर मनोरंजन बैंग लिखा था। एक कैश काउंटिंग मशीन, 7.5 लाख नकद, 4.50 लाख बैंक में फ्रीज राशि और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दक्षिणी जिले के डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार छह जुलाई को एक व्यक्ति ने सीआर पार्क में शिकायत दी कि वह एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था और इसके लिए अपने परिचितों से पैसे जुटाए थे। चार जुलाई को उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने खुद को बैंक में जमा धनराशि को नकद में बदलने वाले बताए। एक फ्लैट में उसे बुलाकर नकदी दिखाकर विश्वास में लिया और उससे 40 लाख रुपये अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। बदले में उसे एक बैग में नकदी दी गई जो कैश काउंटिंग मशीन में गिनी भी गई थी। लेकिन जब उसने बैग खोला तो उसमें केवल मनोरंजन बैंक के नकली नोट थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया। इंस्पेक्टर गिरीश चंद्र की देखरेख में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजेक्शन की गहराई से विश्लेषण किया गया। नौ जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सैदुलाजाब स्थित एक फ्लैट से तीन आरोपित निखिल, प्रिंस पाल और परवेज को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन असगर खान को भी उसी फ्लैट से दबोचा गया।

एमसीडी दिल्ली में 7 लाख से अधिक पौधे लगाएगी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने ग्रीन एक्शन प्लान के तहत पौधारोपण अभियान की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और हरित राजधानी के संकल्प के साथ इस साल दिल्ली में 7 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने एक बयान में बताया कि ग्रीन एक्शन प्लान के तहत वर्ष भर में कुल 7,03,298 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 3 लाख पेड़, 4 लाख झाड़ियां और 3,298 बांस के पौधे शामिल हैं। इस अभियान को मानसून सीजन में गति दी गई है।उन्होंने बताया की अब तक दिल्ली के विभिन्न 12 जोनों में 66,242 पौधे रोपे जा चुके हैं। जिनमें 21,493 पेड़, 41,918 झाड़ियां और 2,831 बांस के पौधे हैं। सत्या शर्मा ने कहा कि नगर निगम के उद्यान विभाग ने बारिश के मौसम में अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू किया है। यह अभियान दिल्ली की हवा को साफ करने, तापमान में कमी लाने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शर्मा ने बताया की ग्रीन एक्शन प्लान को लेकर उद्यान विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है। बैठक में इस वर्ष निर्धारित पौधारोपण लक्ष्य की पूर्ति, उपयुक्त स्थलों का चयन, पौधों की देखरेख और उनके संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए की इन पौधों को चरणबद्ध और सुनियोजित तरीके से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाएगा। सत्या शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का विशेष

उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्लीवासियों से अपील है कि वे अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। यह पर्यावरण सेवा के साथ-साथ मातृ भक्ति का प्रतीक बन सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर दिल्ली को हरा और स्वच्छ बनाना है। सभी दिल्लीवासी इस हरित आंदोलन का हिस्सा बनें। यह सिर्फ पौधा लगाने का काम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुंदर दिल्ली की नींव रखने जैसा है।

दिल्ली को मेडिकल हब बनाना सरकार का लक्ष्यः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को मेडिकल हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार सात अधूरी अस्पताल परियोजनाओं को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्रों में बदल रही है, जहां विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी उत्तरी दिल्ली स्थित मॉडल टाउन क्षेत्र में नवनिर्मित यथार्थ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ही नहीं कर रही, बल्कि उसे सुलभ, पारदर्शी और जन-संवेदनशील भी बना रही है। सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर राजधानी को एक मॉडल हेल्थकेयर सिस्टम की ओर ले जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्लीवासियों को तो बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, साथ ही देश की राजधानी को हम ऐसे मेडिकल

हब में बदले, जहां देश-विदेश से लोग इलाज कराने आएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली सरकार सात अधूरी अस्पताल परियोजनाओं को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्रों में बदल रही है, जहां विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा होगी। हर अस्पताल को अलग बीमारी के इलाज के लिए समर्पित किया जाएगा, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट या डिलीवरी के जटिल मामले। इसके साथ ही आईसीयू बेड्स की कमी को भी दूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार व विजन की कमी की वजह से दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा अभी भी अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कोविड काल को याद करते हुए बताया कि उस समय अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी थी और कई लोगों को इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर स्थिति में रही। उस समय प्रति 1,000 नागरिकों पर केवल 0.42 अस्पताल बेड उपलब्ध थे। 38 सरकारी अस्पतालों में केवल छह एमआरआई और 12 सीटी स्कैन मशीनें थीं, जो किसी भी महानगर के लिए बेहद चिंता की बात है।

दिल्ली सरकार ने 65 से ज्यादा ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को दी राहत

डीपीसीसी से मिलने वाली स्वीकृत देरी को किया खत्म

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने 65 से ज्यादा ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से मिलने वाली स्वीकृत में होने वाली देरी को खत्म कर दिया है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए अगस्त से ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) देने की समय-सीमा 120 दिन से घटाकर 20 दिन करने की घोषणा की। नए सिस्टम के तहत

अगर आवेदन 20 दिन के भीतर स्वीकृत नहीं होता, तो उसे स्वीकृत माना जाएगा।मंत्री ने कहा कि यह दिल्ली के व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और आज डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया जो 50 सालों में नहीं हुआ। यह सिर्फ रिफॉर्म नहीं, बल्कि दिल्ली की उद्योग नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है। उन्होंने कहा कि यह सुधार 65 से अधिक ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा देगा, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स (बिना डाई या ब्लीचिंग के), ऐलुमिनियम और पीवीसी यूनिट्स, बॉयलर के बिना आयुर्वेदिक दवाइयां, कोल्ड स्टोरेज, लकड़ी और स्टील के फर्नीचर, इलेक्ट्रिक ओवन वाली कन्फेक्शनरी यूनिट्स, ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, खिलौने, साबुन और डिटर्जेंट, बैटरी कंटेनर, कार्डबोर्ड और पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग आदि शामिल है।

मामूली कहासुनी में मिस्त्री ने पेट्रोल फेंका, आग लगने से पीड़ित घायल

एजेंसी

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र में रात एक बाइक मिस्त्री ने मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़ित व्यक्ति को झुलसी हुई अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घायल की पहचान वसंत गांव निवासी राहुल चौहान (40) के रूप में हुई है। राहुल पेशे से नगर निगम (एमसीडी) में सफाई कर्मचारी हैं।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल के अनुसार रविवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि सेक्टर-8 की मार्केट में एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पहुंची। घटनास्थल पर पाया कि एक व्यक्ति बुरी तरह झुलसा हुआ था।

उसे तत्कालत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भिजवाया गया। हादसे के वक्त वह अपने चचेरे भाई सिद्धांत राज और दो अन्य लोगों के साथ सेक्टर-8 मार्केट में एक मारुति बलेनो कार के अंदर बैठे हुए थे। कार बाजार की एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान के पास खड़ी थी। पीड़ित के भाई सिद्धांत राज ने पुलिस को बताया कि कार जिस दुकान के पास खड़ी थी। वह दुकान पालम गांव निवासी प्रसाद उर्फ कालू (42) की है। वह दोपहिया वाहन मिस्त्री है। प्रसाद ने कथित तौर पर राहुल और उसके साथियों को कार वहां से हटाने को कहा।

केरल नगर पालिका के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के महापौर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की ली जानकारी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मुख्यालय सिविक सेंटर में केरल के रामनाथुकारा नगर पालिका के 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का उद्देश्य एमसीडी द्वारा अपनाई गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करना था। बैठक के दौरान महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम की नागरिक सेवाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी रणनीतियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दिल्ली जैसे विशाल और सघन आबादी वाले नगर क्षेत्र में एमसीडी नवाचार, कार्यकुशलता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमसीडी अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को निगम की व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 11,500 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है। जिसमें से लगभग 8,000 मीट्रिक टन का निपटान अपशिष्ट-से-ऊर्जा, कम्पोस्टिंग तथा अन्य वैज्ञानिक

विधियों से किया जाता है। शेष 3,500 मीट्रिक टन के निपटान हेतु निगम द्वारा नई, तेज और टिकाऊ तकनीकों को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल को कचरा उत्पत्ति से लेकर उसके प्राथमिक एवं द्वितीयक पृथक्करण, परिवहन और अंतिम निपटान की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने ओखला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का दौरा कर निगम की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। रामनाथुकारा नगर पालिका के प्रतिनिधिमंडल ने एमसीडी द्वारा साझा की गई विस्तृत जानकारी की सराहना की और कहा कि वे इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनी नगर पालिका में अपनाकर शहरी शासन को सुदृढ़ बनाने और सेवा वितरण को बेहतर करने का प्रयास करेंगे।

कांवड़ यात्रा सांस्कृतिक संस्कारों की प्रतीक : मुख्यमंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का वह पावन संगम है, जो दिल्ली की सड़कों को तीर्थ बना देती है। यह परंपरा हमारे जीवंत सांस्कृतिक संस्कारों की प्रतीक है।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि इस यात्रा को सहज, सुलभ, सम्मानजनक और भव्य बनाने का अवसर दिल्ली सरकार को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सावन के पहले सभी शिवभक्तों को मंगलकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ शिविरों की व्यवस्था परखने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इस बार दिल्ली के लोगों में कांवड़ियों के स्वागत का विशेष सेवा भाव है, इसीलिए इस बार शिविर लगाने के लिए 374 आवेदन मिले हैं। इस बार दिल्ली सरकार ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाया और एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया। अब किसी संस्था को अलग-अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़े और सभी को मात्र 48 से 70 घंटों में अनुमति मिल गई।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने इस वर्ष शिविरों को बिजली आपूर्ति के लिए 1200 यूनिट तक निशुल्क सुविधा दी है। इसके अलावा, टॉयलेट्स की पूरी व्यवस्था सरकार स्वयं कर रही है, जिसमें 24 घंटे तैनात सफाईकर्मी भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे कांवड़ शिविरों में स्वच्छता और सुविधा का नया मानदंड स्थापित होगा।

इसके अतिरिक्त शिविरों में स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो पास के अस्पतालों से समन्वय बनाकर सेवाएं देंगी। साथ ही यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम द्वारा सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई हैं।

सरकार के लिए पीएसी और सीएजी अलार्म का काम करती है : विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) एक अलार्म की तरह काम करती हैं, जिनका उद्देश्य सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह बात दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेघालय विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान विधानसभा परिसर में कही। यह प्रतिनिधिमंडल 12 से 14 जुलाई तक हैदराबाद, विशाखापत्तनम और दिल्ली के अध्ययन दौरे पर है। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अंतर-विधायी संवाद और ज्ञान साझाकरण के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चार्ल्स पायंगरॉप, लाहकमें रिंबुई, गेविन मिगुएल मायलियेम, रूपर्ट मोमिन, रूपा एम मारक, सेंगचिम एन संगमा, जिमी डी संगमा, इयान बोथम के संगमा एवं बालाजिएद कूपर सिनरेम शामिल रहे। इस दौरे का उद्देश्य अन्य राज्य विधानमंडलों के साथ विचारों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और लोक

लेखा समिति के सभापति अजय महावर भी बैठक में उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुप्ता ने मेघालय की जनसांख्यिकी और लोक लेखा समिति की संरचना के बारे में जानकारी ली। इस पर चार्ल्स पायंगरॉप ने बताया कि मेघालय एक मातृसत्तात्मक राज्य है, जहां मुख्य रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां निवास करती हैं। यह राज्य संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित होता है, जो जनजातीय हितों की रक्षा करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष सहित कुल दस सदस्य हैं, और आम तौर पर संतुलित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष विपक्ष से होता है। विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली विधानसभा में लागू ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी, जो वित्तीय जवाबदेही को सशक्त बनाता है। इस दौरान मेघालय की पीएसी के सदस्यों ने वित्तीय निगरानी पर अपने विचार साझा किए।

आपसी झगड़े में दो दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, दोनों की मौत

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिमी जिले के तिलक नगर इलाके में रात आपसी झगड़े ने दो दोस्तों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक बी-ब्लॉक, ख्याला के रहने वाले थे। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे। रविवार रात करीब 11 बजे दोनों दोस्त तिलक नगर स्थित पार्क में बैठे थे। इसी दौरान किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में तब्दील हो गई। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि हाथापाई के दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला किया। झगड़े में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों को तुरंत दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई कि बी-ब्लॉक से दो लोगों को चाकू से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों घायलों को भर्ती तो किया गया, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर है। देर रात इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जांच में मृतकों की पहचान आरिफ और संदीप के रूप में हुई है। दोनों ख्याला (बी ब्लॉक) के रहने वाले थे और एक ही गली में रहते थे। पश्चिमी जिले के डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की बारीकी से जांच की जा रही है।

पुलिस टीम ने स्थानीय स्तर पर पूछताछ भी की है। जिससे झगड़े की असली वजह का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पड़ोसियों व प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ कि आपसी विवाद जानलेवा झगड़े में तब्दील हो गया। पुलिस कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, दोनों शादीशुदा थे। जांच में पता चला है कि संदीप का प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार था और वह पहले एक जिम ट्रेनर भी रह चुका है। वहीं आरिफ प्राइवेट कंपनी में काम करता था।

संपादक की कलम से

बिहार तो बस झांकी है, पूरा देश बाकी है!

बिहार में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र निवासी प्रमाणपत्र पर या तो जन्म की तिथि नहीं होती या निवास का पता नहीं लिखा होता है। ये दो चीजें ही मतदाता बनने के लिए चाहिए। फिर इन तीन में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर कोई मतदाता कैसे बन पाएगा? इसके अलावा दो दस्तावेज हैं एनआरसी और फैमिली रजिस्टर। एक समय था जब भारत के चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख थी। ऐसी साख कि दुनिया के जिन देशों में संसदीय लोकतंत्र पहले से है या जिन्होंने बाद में उसे अपनाया, वे सारे भारतीय चुनाव आयोग को निमंत्रण देकर अपने यहां बुलाते थे और अनुरोध करते थे कि वह आए और उनके यहां के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करे कि निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाते हैं। ऐसे अनुरोधों पर भारत का चुनाव आयोग अपने अधिकारियों का दल संबंधित देशों में भेजता भी था। कई देश भारत में चुनाव के समय अपने यहां के चुनाव अधिकारियों को भारत के दौरे पर भेजते थे, यह देखने के लिए भारत का चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराता है। यह सिलसिला अब बंद हो चुका है, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग अपनी साख पूरी तरह गंवा चुका है। कहने को तो चुनाव आयोग अभी भी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है लेकिन पिछले एक दशक से वह व्यावहारिक तौर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक विभाग में तब्दील हो गया है। इसकी ताजा मिसाल बिहार में देखी जा सकती है, जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया है, जो स्पष्ट रूप से एक तर्कहीन और हास्यास्पद तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि चुनाव आयोग की नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसने अपनी इस कवायद पर बिहार के विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की आपत्तियों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की राह आसान करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहे इस तमाशे का स्पष्ट मकसद बड़ी संख्या में गरीब, वंचित अल्पसंख्यक तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग बिहार के लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाणपत्र मांग रहा है। इस सिलसिले में उसका कहना है कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज करा सकता। इन तीन के अलावा चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। इन 11 में से कोई एक दस्तावेज मतगणना प्रपत्र के साथ जमा कराना है। इनमें सरकारी नौकरी या संपत्ति आदि के दस्तावेजों को छोड़ दें तो कई दस्तावेज ऐसे हैं, जिन्हें बनवाने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होता है। यानी आधार कार्ड के सहारे कोई व्यक्ति जो दस्तावेज बनवाएगा, उनसे वह मतदाता बन सकता है लेकिन सीधे आधार कार्ड के आधार पर मतदाता नहीं बन सकता। गौरतलब यह है कि बिहार में आवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड ही एकमात्र दस्तावेज है। यानी कोई आधार लेकर जाएगा तो उसका आवास प्रमाणपत्र बन जाएगा और वह आवास प्रमाणपत्र चुनाव आयोग की ओर से वांछित 11 दस्तावेजों में से एक है। यानी उसे जमा करा कर कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है। पिछले 15 दिनों में लाखों लोगों ने आधार कार्ड के जरिए अपना आवास प्रमाणपत्र बनवाने का आवेदन किया है। इनमें से 10 फीसदी के भी प्रमाणपत्र 25 जुलाई तक नहीं बन पाएंगे। इससे जाहिर है कि चुनाव आयोग ने लोगों को परेशान करने के लिए यह कवायद शुरू की है। अगर आधार कार्ड के जरिये आवास प्रमाणपत्र बन सकता है और उससे मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकता है तो फिर सीधे आधार कार्ड के दम पर मतदाता बनाने में क्या समस्या है? मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर जिन मान्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने की इजाजत है उनमें आधार और मनरेगा कार्ड दोनों हैं। लेकिन बिहार में इन दोनों के आधार पर मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों के आधार पर देश के दूसरे हिस्सों में मतदाता पहचान पत्र बनाया जा सकता है।

अह्लरङ्ग फीं- अब मतदाता सूचियों में विदेशी नामों का हौवा कायदे से चुनाव आयोग को अगर यह काम करना ही था तो इसकी शुरूआत जनवरी में करनी थी, मतदाताओं को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था और राजनीतिक दलों को भी भरोसे में लेना था। 22 साल पहले 2003 में भी चुनाव आयोग ने यह काम किया था, जिसमें उसे दो साल लगे थे लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने वही काम करने के लिए एक महीने की अवधि निर्धारित की है।

अमेरिका में बढ़ रहे कोरोना के मामले, इस वेरिएंट से खतरा

कोरोना वायरस एक बार फिर अमेरिका में चिंता का कारण बन रहा है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के करीब 25 राज्यों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं. इस बार यह बढ़ोतरी गर्मियों में देखी जा रही है, जिसे विशेषज्ञ समर वेव कह रहे हैं. हेल्थ एजेंसियों के अनुसार, केसों की संख्या, वेस्टवॉटर निगरानी और अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि संक्रमण फिर से तेजी पकड़ रहा है. इसके पीछे कारण है एक नया वेरिएंट, जो पहले की तुलना में तेजी से फैल रहा है. लोगों में सावधानी की कमी, टीकाकरण के प्रति लापरवाही और छुट्टियों के दौरान भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने की आदत भी केसों में इजाफा कर रही है.

इस समय अमेरिका में जिस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ रही है, वह ठइ.1.8.1 है, जिसे ह्लठ्ठे४२ह्व कहा जा रहा है. इसके अलावा कुछ अन्य सब-वेरिएंट्स जैसे छढ.8.1 और ऋक्र भी सामने आए हैं. ये सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही प्रकार हैं, लेकिन इनकी ट्रांसमिशन क्षमता अधिक है, यानी ये तेजी से फैल सकते हैं. राहत की बात यह है कि अब तक इन वेरिएंट्स से संक्रमित अधिकतर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं. हालांकि, बुजुर्गों, पहले से बीमार व्यक्तियों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह वेरिएंट जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में सतर्क रहना और बचाव के तरीके अपनाना बेहद जरूरी है.

नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं?

NB.1.8.1 ?? 'Nimbus' वेरिएंट के लक्षण पहले आए कोविड वेरिएंट्स जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ नए और अलग तरह के लक्षण सामने आए हैं जो इसे थोड़ा अनोखा बनाते हैं. सबसे प्रमुख लक्षण है गले में तेज जलन या चुभन, जिसे लोग ह्ल१९ड्ढ१-ह्लीं ३ँ१ड्ढं३ह्व कह रहे हैं यानी ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कुछ चुभ रहा हो या तेज जलन हो रही हो. यह तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि निगलने में भी परेशानी होने लगती है.

इसके अलावा तेज बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द और थकान जैसे सामान्य लक्षण भी देखे जा रहे हैं. कुछ लोगों को भूख में कमी, नींद न आना और हल्का डिप्रेशन भी महसूस हुआ है. खास बात ये है कि खांसी और सांस फूलने जैसे गंभीर लक्षण इस वेरिएंट में अभी तक कम दिखे हैं, लेकिन अगर कोई पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा है या पहले कोविड से ग्रस्त रह चुका है, तो इस वेरिएंट के लक्षण उसमें ज्यादा तेज रूप ले सकते हैं. अपना कोविड वैक्सीनेशन अपडेट रखें, खासकर बूस्टर डोज लें.

भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनें, खासकर एयरपोर्ट, बस या ट्रेन में.

कांवड़ यात्रा का अब राजनीतिक कनेक्शन

राकेश अचल

सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में एक 'कांवड़ यात्रा' 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है. कांवड़ यात्रा की शुरूआत होती ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत भी गरमा गई है. दरअसल, बीते तीन से चार दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुईं, जब कांवड़ियों ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल-ढाबों पर तोड़फोड़ की. इस दौरान कांवड़ियों ने ढाबा मालिकों पर मुस्लिम व्यवसायियों पर पहचान छिपाकर ढाबा संचालित करने का आरोप लगाया.

कांवड़ यात्रा का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो सावन मास (जुलाई-अगस्त) में होती है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा है।लेकिन कोई एक प्रामाणिक कथा कांवड की नहीं है.

कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जोड़ी जाती है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें से विष (हलाहल) निकला। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने शिव पर गंगा जल चढ़ाया। माना जाता है कि कांवड़ यात्रा इस घटना का प्रतीक है, जिसमें भक्त गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार, भगवान परशुराम ने अपने आराध्य शिव की पूजा के लिए गंगा जल लाने की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने कांवड़ (एक बांस के डंडे पर दो बर्तनों में जल) के साथ गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, जिससे यह परंपरा प्रचलित हुई।वैसे त्रेता युग की कथाओं में श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता कोयात्रा कांवड यात्रा देश के दूसरे हिस्से में प्रचलित नहीं है.द्वारा तीर्थ यात्रा कराने का जिक्र है.

कांवड़ यात्रा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन यह माना जाता है कि यह परंपरा मध्यकाल से प्रचलित है। सावन मास में शिव भक्ति और गंगा जल के महत्व को देखते हुए यह यात्रा धीरे-धीरे लोकप्रिय हुई। कांवड़ यात्रा ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भक्ति, समर्पण और तप का प्रतीक बन गई, जिसमें सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेते हैं। कांवड यात्रा में भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, या अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल चलकर प्रमुख शिव मंदिरों जैसे नीलकंठ, काशी विश्वनाथ, या बैद्यनाथ धाम जाते हैं।कांवड बांस से बनाई जाती है. बांस के डंडे के दोनों सिरों पर जल से भरे बर्तन लटकाए जाते हैं। इसे कंधे पर रखकर भक्त यात्रा करते हैं।

कांवड़िए कठोर नियमों का पालन करते हैं, जमीन पर न सोना, शुद्ध भोजन करना और गंगा जल को भूमि पर न रखना शामिल है. कांवड़ यात्रा उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और बिहार में बड़े पैमाने पर आयोजित होती है। लाखों भक्त इसमें हिस्सा लेते हैं, और यह एक विशाल सामाजिक-धार्मिक आयोजन बन गया है। आधुनिक समय में, कांवड़ यात्रा में ट्रैक्टर, बाइक और अन्य वाहनों का उपयोग भी होने लगा है, हालांकि पारंपरिक पैदल यात्रा अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।पिछले कुछ वर्षों से कांवड यात्रा एक राजनीतिक आयोजन हो गया है. सरकार कांवडियों पर हैलीकाप्टर से पुष्प वर्षा करने लगी है. इस यात्रा का इस्तेमाल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए भी होने लगा है. मजे की बात ये है कि जिस कांवड यात्रा को राजनीतिक इवेंट बना दिया गया है उसमें सत्ताधारी दल का एक भी छोटा, बडा नेता या उनके बच्चे शामिल नहीं होते. यह श्रमसाध्य कार्य केवल समाज के पिछडे, अशिक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवा करते है. अब कांवडिये जरा जरा सी बात पर सरकारी संरक्षण में जिस तरह का उपद्रव करते हैं उसे देखकर आशंका होती है कि एक सात्विक परंपरा का सत्यानाश हो रहा है. इस यात्रा को भाजपा ने एक तरह से अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है.

यह पहली बार नहीं है जब कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का विवाद सामने आया है. इससे पहले भी मुस्लिम ढाबा संचालकों पर हिंदू नाम से व्यवसाय करने के आरोप लगाए गए हैं. कुछ मामले साबित भी हुए हैं तो कुछ फर्जी भी निकले. ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम होकर हिंदू नाम से ढाबा चलाना क्या गैरकानूनी है? और इस मामले में कानून क्या कहता है? भारत संविधान के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार है. जहां तक होटल या ढाबों की बात है तो इसके लिए खाद विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें होटल या ढाबा संचालक का नाम लिखा होता है. सभी होटल या ढाबा संचालकों को यह लाइसेंस रखना अनिवार्य होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी जांच की जा सके. भारतीय कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य नाम से व्यवसाय संचालित करना अपराध नहीं है. हालांकि, अगर ऐसा समाज में भ्रम फैलाने या किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत होटल या ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की जा सकती है.

बीते साल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल या ढाबा संचालकों को अपना नाम व होटल पर काम करने वाले कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था. सरकार का कहना था कि यह आदेश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया, जिससे कांवड़ यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति न हो और विवाद से बचा जा सके. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पर रोक लगा दी थी कि सरकार किसी होटल या ढाबा संचालकों को नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, अगर वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं.।

पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र पर्व की चर्चाएं पूरी दुनियाँ में होतीरहती है,जो भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती है, परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, इस प्रतिष्ठा में निखार लाने के लिए इसकी त्रुटियां, लीकेजेस, जाली मतदाताओं को पहचान कर सुचियों का पुनरीक्षण,शुद्धिकरण करना समय की मांग है, जिसका क्रियान्वयन बिहार से शुरू हो चुका है जहां 2025 के अंत तक चुनाव होने की चर्चाएं चल रही है वैसे तो, इस तरह के बड़े पुनरीक्षण अभियान पहले भी कई बार हो चुके हैं,1950 के दशक से लेकर 2004 तक कई बार।लेकिन इस बार काअभियान दो वजहों से अलग है- पहली बार पहले से रजिस्टर्ड वोटर से ही दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और दूसरी बार आयोग ने खुद अपनी पुरानी वोटर लिस्ट की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में देशभर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है,और आम लोगों को फिर से खुद को साबित करने के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि शहरों मेंपलायन बढ़ा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, लेकिन पुराने पते से नाम नहीं हटवाते। इससे एक ही व्यक्ति के नाम दो जगह आ जाते हैं। इसी को ठीक करने के लिए वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने भी कई बार फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आयोग का कहना है कि इस तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए ही ये अभियान जरूरी है। बिहार में अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे थे। इनमें आधार, वोटर

आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और कुछ सरकारी पहचान पत्र शामिल थे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ आधार,राशन कार्ड और वोटर आईडी ही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब आयोग ने तीन दस्तावेज-आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड,को भी शामिल करने पर विचार किया है। ये दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास हैं,खासकरबिहार जैसे राज्यों में।बिहार में चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची का ह्यविशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।लेकिन इसी बीच आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के बाकी सभी राज्यों को भी ऐसी ही तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वे 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर मतदाता सूचियों को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करें। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि, इस पूरे अभियान की टाइमलाइन अभी तय नहीं हुई है चूँकि बिहार में 2003 की मतदाता सूचि को प्रमाणिक आधार मानकर संभावित 2.93 करोड़ वर्तमान मतदाताओं पर असर पड़ने की संभावना है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, बिहार में चौकाने वाले आंकड़े आए हैं,35.5 लाख, मतदाताओं के नाम संभव तो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभवतः करोड़ों मतदाताओं के नाम मृत्यु, एक से अधिक सूचियां में नाम दर्ज, जाली प्रमाण व आधार के कारण हटाने से पारदर्शिता बढ़ेगी।साथियों बात अगर हम बिहार में चल रहे एसआईआर की करें तो 14 जुलाई 2025 को देर रात आई जानकारी के अनुसार, बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत 35.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के ताजे आंकडों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं जबकि 2.2 प्रतिशत मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। इसके साथ ही 0.73 प्रतिशत व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। जिनका कुल योग 4.52 फीसदी है। जो कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में 35.5 लाख हैं।सोमवार को चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत अबतक 83.66 प्रतिशत मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए गए हैं। इस प्रकार, 88.18 पेर्सेंट मतदाताओं ने या तो गणना फॉर्म जमा कर दिया है, या मृत पाए गए हैं, या फिर एक स्थान पर नाम बरकरार रखा गया है अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं।अब केवल 11.82 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा गणना फॉर्म जमा किया जाना शेष है। इनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने के लिए समय मांगा है। 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। इसके बाद ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। इसी सूची के आधार पर 2025 के चुनावों की मतदाता सूची तय होगी।चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए गए प्लेटफॉर्म पर अब तक 5.74 करोड़ से अधिक फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म जो पहले की 40 चुनावी ऐप्स को समाहित कर एकीकृत किया गया है।अब ऑनलाइन फॉर्म भरने, नाम खोजने, और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपयोग हो रहा है। अब तीसरे चरण में लगभग 1 लाख बीएलओ एक बार फिर घर-घर जाएंगे।सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। प्रत्येक बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन 50 गणना पत्र तक जमा और प्रमाणित कर सकता है। 261 नगर निकायों के 5,683 वार्डों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र शहरी मतदाता सूची से बाहर न रहे ऐसा पूरा प्रयास हो रहा है। साथियों बात अगर हम पूरे भारत में एसआईआर लागू करने की करें तो,फिलहाल जो संकेत मिल रहे है, उनमें अगले दो सालों में इसे चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में लेकर वह जाएगा। जिसकी शुरूआत अगले महीने से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल सहित पांच राज्यों से हो सकती है। इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी है। इस पूरे अभियान को लेकर सबसे ज्यादा डर हाशिए पर जी रहे लोगों में है। ईबीसी, दलित, मुसलमान और गरीब तबके के लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम ही न कट जाए। कुछ इसे पीछे से लाया गया एनआरसी कह रहे हैं। मतलब बिना सीधे कहे नागरिकता की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इस प्रक्रिया को रोकने से तो मना कर दिया, लेकिन चिंता जताई कि कहीं चुनाव से पहले किसी का नाम लिस्ट से हट गया, तो उसका वोट देने का अधिकार ही छिन जाएगा। कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया कि दस्तावेजी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे।कि पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा-बिहार में चौकाने वाले आंकड़े आए 3.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरूबिहार में 2003 की मतदाता सूची को प्रमाणिक आधार माना- संभावित 2.93 करोड़ वर्तमान मतदाताओं पर असर पड़ने की संभावना?पूरे भारत की मतदाता सूचियों में संभवतःकरोड़ों मतदाताओं के नाम मृत्यु, एक से अधिक सूचियां में नाम दर्ज, जाली प्रमाण व आधार के कारण हटाने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

शिक्षा में भारतीय ज्ञान का समावेश: क्यों और कैसे?

सुनने में यह कुछ अटपटी सी बात लगती है कि भारतीय शिक्षा को अब 'भारतीय' ज्ञान-परम्परा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पहल की जा रही है। इसे लेकर आम आदमी के मन में कई सवाल खड़े होते हैं। भारतीय होने का क्या अर्थ है ? जो ज्ञान-परम्परा स्वतंत्र भारत में चलती रही है वह किस अर्थ में भारतीय नहीं थी या कम भारतीय थी ? भारतीय ज्ञान-परम्परा का स्वरूप क्या है ? वह किस रूप में दूसरी ज्ञान-परम्पराओं से अलग है ? इस भारतीय ज्ञान-परम्परा की विशिष्टता क्या है जो हम इसकी ओर मुड़ें ? हालांकि इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कुछ राजनीतिक पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है पर आज के ज्ञान-युग में सामर्थ्यशाली होने के लिए इस पर विचार करना भारत के लिए किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं कहा जा सकता। शिक्षा भारत में हो रही है, वह भारतीय शिक्षार्थियों के लिए है और भारतीयों द्वारा ही दी जा रही है। यह लोक-रुचि और लोक-कल्याण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस पर सार्वजनिक विचार होना ही चाहिए । तटस्थता और उपेक्षा का नजरिया छोड़ कर इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है। आखिरकार यह पूरे समाज की मनोवृत्ति, आचरण और देश के सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल है। शिक्षा की दृष्टि से यह एक गंभीर तथ्य हो जाता है कि हम आलोचनात्मक रूप से चिंतनहीन और सर्जनात्मकता की दृष्टि से पंगु होते जा रहे हैं। शैक्षिक निष्पादन चिंताजनक रूप से घट रहा है। राजनीति में आडम्बर और मानवीय मूल्य दृष्टि की बढ़ती कमी आज सबको खटक रही है। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में चिन्ताएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था में आज तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका । आज करोड़ों मुकदमें हैं जिनमें झूठे मुकदमे भी हैं और करोड़ों परिवार त्रस्त हैं। नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हैं। ऐसे में शिक्षा पर बहुतों की नजरें टिकी हैं और उसके सुधार से बड़ी आशाएं जगती हैं। शिक्षा नीति में भारतीयता की दिशा में बदलाव की पहल के प्रति समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान को सार्वभौमिक मान रहे लोग इसे राजनैतिक शगूफा मान रहे हैं, कुछ इस मोड़ के प्रति तटस्थ हैं, कुछ थोड़े संभ्रम के साथ उत्सुक हैं। कुछ हैं जो वास्तविक अर्थों में इसे गंभीरता से भी ले रहे हैं पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । जो भी हो भारतीय ज्ञान-परम्परा का नीति-निर्माण की दुनिया में प्रवेश हो चुका है। नई शिक्षा नीति को लेकर देश भर में हुई लगातार हुई चचाओं के कई दौर चलने के बाद विभिन्न विषयों के पाठयक्रम भारतीय ज्ञान-परम्परा के प्रति उन्मुख हो रहे हैं और आम जनों के बीच भी इसे लेकर उत्सुकता बढी है। पर शिक्षा में भारतीयता की इस सतही उपस्थिति से आगे बढ कर गम्भीर और व्यवस्थित रूप इस उपक्रम को अभी तक नहीं मिल सका है।

कई लोग इसे एक नारा मान कर चल रहे हैं जब कि कुछ के लिए यह अस्मिता और भावना का प्रश्न बन गया है।

यह तो तय है कि यदि पश्चिमी खचीर्ले और अंशतः दिशाहीन तथा आयातित ज्ञान को थोपे जाने से मुक्ति की इच्छा है और अपने देश के ज्ञान, कौशल और अस्मिता को बंधक से छुड़ाने का मन है तो शिक्षा में बदलाव लाना ही होगा। यह भी निर्विवाद है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मानसिक स्वराज जरूरी है और अपनी ज्ञान-व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा।

ओढ़ी हुई आधुनिकता की जगह नवोन्मेषी हो कर समकालीन परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी लाना होगा। हमको सांकेतिक और सजावटी बदलाव के भुलावे से आगे बढ़कर परिस्थितियों का सामना करना होगा और शिक्षा में जरूरी रूपांतर भी लाना होगा क्योंकि मानसिक गुलामी कई तरह से देश को आहत करती आ रही है जिसका बहुतों को पता भी नहीं होता। भारत के मानस का वि-उपनिवेशीकरण

(डिकोलोनाइजेशन) शिक्षा में भारतीय दृष्टि की विवेकपूर्ण संगति के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है। भारत की शिक्षा को भारतीय दृष्टि में स्थापित करने के परिणाम भारत और विश्व दोनों के ही हित में होगा। ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के पश्चिमी माडेल का खोखलेपन दिन-प्रतिदिन उजागर हो रहा है।

यूक्रेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी यूलिया स्विरीडेन्को

एजेंसी

कीव। यूक्रेन की अगली प्रधानमंत्री यूलिया अनातोलीवना स्विरीडेन्को होंगी। सोवियत संघ के चेर्निगोव में 25 दिसंबर, 1985 को जन्मीं यूलिया इस समय यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री (प्रथम) हैं। वो मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल का स्थान लेंगी। उनके जन्मस्थान का नाम बदलकर चेर्निहीव हो चुका है। चेर्निहीव अब यूक्रेन में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनकी नई जिम्मेदारी तय की है। जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में लिखा, मैंने प्रस्ताव दिया है कि यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन सरकार का नेतृत्व करें। वह प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। मैं निकट भविष्य में नई सरकार की कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूलिया स्विरीडेंको के साथ बैठक की। हम दोनों ने यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में यूरोपीय और अमेरिकी साझेदारों के साथ हुए समझौतों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पर चर्चा की। हम दोनों ने यूक्रेन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने, यूक्रेनवासियों के लिए सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने और घरेलू हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के ठोस उपायों पर भी चर्चा की।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर जताई चिंता

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि वैश्विक वकास से जुड़े केवल 35 प्रतिशत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) ही तय समय तक हासिल होने की दिशा में हैं, जबकि शेष लक्ष्य या तो धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक विकास का आपातकाल बताया। महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 जारी करते हुए संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें कहीं। उन्होंने बताया कि बीते दस वर्षों में शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बाल विवाह में कमी आई है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि 80 करोड़ से अधिक लोग अब भी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। लगभग 18 प्रतिशत लक्ष्य पीछे की ओर जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ऋण संकट और संघर्षों ने विकास की गति को बाधित किया है। महासचिव ने गाजा, यूक्रेन, सूडान और पश्चिम एशिया में शांति की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव ली जुनहुआ ने रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2010 के मुकाबले नए एचआईवी संक्रमण में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है और 2000 से अब तक मलेरिया रोकथाम से 1.2 करोड़ जीवन बचाए गए हैं। 2015 से अब तक 11 करोड़ से अधिक बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ है।

अमेरिकी शिक्षा विभाग में छंटनी का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप खुश

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन अब संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग में अपने हिसाब से छंटनी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन को शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना को अनुमति प्रदान कर दी। इस योजना पर पहले एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी। रूढ़िवादी बहुमत वाली शीर्ष अदालत ने बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रशासन की आपातकालीन अर्जी को स्वीकार कर लिया। एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, शीर्ष अदालत के तीन उदारवादी सदस्यों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति सोनिया सोतोमयोर ने तो तीखी असहमति व्यक्त की। उन्होंने लिखा, कार्यपालिका ने सार्वजनिक रूप से कानून तोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की है। न्यायपालिका का कर्तव्य यह है कि उसे ऐसा करने से रोके ना कि मनमानी करने की छूट दे। सोतोमयोर ने कहा, न्यायालय का बहुमत या तो जानबूझकर अपने फैसले के निहितार्थों के प्रति अंधा है या फिर नासमझ है। यह फैसला संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान की स्पष्ट अवहेलना करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा करके देश भर के अभिभावकों और छात्रों को एक बड़ी जीत दिलाई है।

सीरियाई विदेश मंत्री ने आईडीएफ हमलों पर दी परोक्ष प्रतिक्रिया, कहा- बाहरी हस्तक्षेप अनुचित

ब्रुसेल्स। सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने दक्षिणी सीरिया में इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा किए गए टैंक हमलों पर परोक्ष रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को भी सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी उन्होंने सऊदी समाचार चैनल अल-हदथ से बातचीत के दौरान की, जब वे बीते दिनों बेदुइन जनजातियों और ड्रूज़ लड़ाकों के बीच हुई हिंसक झड़पों पर बोल रहे थे। यहीं पर इजराइल ने आज टैंकों पर हमला किया था। विदेश मंत्री शिबानी ने आगे कहा, हथियार उठाना सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरिया धीरे-धीरे फिर से अरब जगत और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट रहा है। असद अल-शिबानी फिलहाल ब्रुसेल्स में हैं, जहां वे यूरोपीय संघ के अधिकारियों से कई अहम बैठकें कर रहे हैं। संयोग से, इज़राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भी वहीं मौजूद हैं, हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी सीधी मुलाकात की योजना नहीं है। गिदोन सार के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्तिगत बैठक निर्धारित नहीं है।

न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश से आई बाढ़, आपातकालीन चेतावनी जारी

एजेंसी

न्यूयॉर्क । उत्तर-पूर्व और मध्य-अटलांटिक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण न्यूयॉर्क शहर और उत्तरी न्यू जर्सी में बाढ़ आ गई है। स्थिति को देखते हुए आपातकालीन चेतावनियां जारी करी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हालात को देखते हुए न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने सोमवार देर रात आपातकाल की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, मैं राज्य के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर रहा हूं। कृपया घर के अंदर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। सुरक्षित रहे, न्यू जर्सी। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने न्यूयॉर्क शहर के सभी पांच बरो के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की, क्योंकि सोमवार शाम तक

भारी तूफान के कारण स्टेटन आइलैंड और मैनहट्टन जैसे क्षेत्रों में एक इंच से अधिक बारिश हुई। न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों ने निवासियों, खासकर बेसमेंट अपार्टमेंट में रहने वालों को अचानक खाली कराए जाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक्स पोस्ट में लिखा, अगर आप बेसमेंट फ्लैट में रहते हैं, तो सतर्क रहें। अचानक बाढ़ बिना किसी चेतावनी के आ सकती है, यहां तक कि रात में भी। अधिकारियों ने कहा कि अपने पास फोन, टॉर्च और जरूरी सामान का बैग रखें। ऊंचे स्थान पर जाने के लिए तैयार रहें।

आंकड़ों के अनुसार, मैनहट्टन के चेल्सी इलाके में शाम 7:30 बजे तक 1.47 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि स्टेटन आइलैंड में 1.67 इंच बारिश हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अधिकारी रात तक हाई अलर्ट पर रहे। शहरों में और बारिश की संभावना है। आपातकालीन टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैनात हैं।

शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी : स्पेसक्राफ्ट की कैलिफोर्निया तट पर लैंडिंग

एजेंसी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में ऐतिहासिक एक्सिओम मिशन-4 पूरा करने के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हो गई है। शुभांशु ने अपने इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में करीब 18 दिन का समय बिताया है. इस दौरान उन्होंने कई प्रयोग भी किए हैं. करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कुछ ही देर में कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हो गई है। बता दें कि शुभांशु शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के तहत तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे।

प्योंगयांग-मॉस्को के बीच सीधी उड़ानें इस महीने से शुरू होंगी : रिपोर्ट

एजेंसी

सियोल । उत्तर कोरिया और रूस इस महीने के अंत में अपनी राजधानियों प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने वाले हैं। एक रूसी समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी ने रूस के परिवहन मंत्रालय के हवाले से तास को बताया कि नॉर्डविंड एयरलाइंस 27 जुलाई से दोनों शहरों को जोड़ने वाली सीधी उड़ानें शुरू करेगी। समाचार एजेंसी ने बताया कि यह पहली बार होगा कि उत्तर कोरिया और रूस की राजधानियां सीधी हवाई सेवा से जुड़ेंगी। रूसी विमानन अधिकारियों ने पिछले महीने नॉर्डविंड को प्योंगयांग और मॉस्को के बीच हफ्ते में दो बार सीधी उड़ानें शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके बाद यह नया हवाई मार्ग शुरू हुआ है। तास ने बताया कि उड़ान का समय लगभग आठ घंटे है। वर्तमान में, उत्तर कोरिया और रूस के बीच केवल प्योंगयांग और व्लादिवोस्तोक के बीच सीधी उड़ानें

हैं। पिछले साल जून में आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार बन गए हैं। इसके बाद से उन्होंने परिवहन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। पिछले महीने, उत्तर कोरिया और रूस ने कोविड-19 के कारण रुकी रेल सेवा फिर से शुरू की, जिसमें प्योंगयांग से मॉस्को और खाबरोव्स्क के बीच सीधी रेल सेवा शामिल है। इसके अलावा, अप्रैल में दोनों देशों ने तुमेन नदी पर एक सड़क पुल का निर्माण भी शुरू किया। पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसन के दौरे के दौरान, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन मार्गों को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है।

भूकंप के झटकों से दहला फिलीपींस, रिक्टर स्केल पर 5.8 दर्ज की गई तीव्रता

एजेंसी

फिलीपींस। फिलीपींस में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। हालांकि, अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

समाचार एजेंसी के अनुसार, मंगलवार सुबह उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्ट प्रांत में 5.8 तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसकी जानकारी फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनो लॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने दी। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार मंगलवार सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर महसूस किए गए।, जिसका केंद्र पासुक्विन शहर से लगभग 29 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में 27 किलोमीटर की गहराई पर था। यह टेक्टॉनिक भूकंप था, जिसके कारण कुछ और झटके आ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना कम है। इस भूकंप का असर पड़ोसी प्रांतों कागायन, इलोकोस सुर, इसाबेला और अब्रा में भी महसूस किया गया। फिलीपींस में बार-बार भूकंप आते हैं, क्योंकि यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है।

फिलीपींस में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं. इनमें ज्यादातर झटके कम तीव्रता के होते हैं। लेकिन पिछले महीने भी फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। 24 जून को दक्षिणी फिलीपींस में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यूएसजीएस के मुताबिक, ये भूकंप दावाओ द्वीप से करीब 374 किमी पूर्व में आया था। इस भूकंप से भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या किसी की जान नहीं गई थी।

फिलीपींस में आने वाले ज्यादातर भूकंप कम तीव्रता के होते हैं। लेकिन 2022 में फिलीपींस में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था। जिससे भारी तबाही मची थी। इस भूकंप में कई इमारतें भरभरा कर गिर गई थीं और तमाम मकानों में दरारें आ गई थीं। इस प्राकृतिक आपदा में 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है।

पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बरसात से तबाही, 15 की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानसून की बारिश ने कहर बरपाया। आंधी-पानी और बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अकेले पंजाब प्रांत में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 62 घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, दोनों प्रांतों में काले बादलों ने आसमान को चीर दिया। मूसलाधार बारिश से अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए। छतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। पिछले 24 घंटों में अकेले पंजाब में कम से कम नौ लोगों की जान चली गई। रावलपिंडी से राजनपुर और उसके आगे बाढ़ जैसा नजारा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत से अब तक देशभर में मानसून से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की

संख्या 111 हो गई है। सैकड़ों घर ढह गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ से बिजली ग्रिड प्रभावित हुए हैं। रावलपिंडी में चकरी इंटरचेंज के पास एम-2 मोटरवे पर एक यात्री बस बारिश फिसलकर पलट गई। इस हादसे में 50 वर्षीय समीना सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ओकारा के नईमाबाद में आसमानी बिजली गिरने से दो किशोरों की मौत हो गई। पंजाब की मिंचिनाबाद तहसील के पाकपट्टन रोड पर बस्ती रशीद कोट में एक मदरसे की छत गिर जाने से दो बच्चों की तत्काल मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, जून के अंत में मानसून के मौसम की शुरुआत के बाद से 53 बच्चों सहित कम से कम 111 लोगों की मौत हो चुकी है।

इस बीच पाकिस्तान के मौसम एवं विज्ञान विभाग ने 17 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मुरी, गल्यात, मनसेहरा, स्वात और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन की चेतावनी जारी की है।

बांग्लादेश ने 34 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश की नौसेना ने कथित तौर पर देश की समुद्री सीमा में प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 34 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है। इनके मछली पकड़ने वाले दोनों ट्रॉलरों तट के पास निगरानी में रखा गया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि इन ट्रॉलरों को सोमवार देर रात गहरे समुद्र में फेयरवे बॉय क्षेत्र के पास रोका गया। ट्रॉलरों से समुद्री मछलियों की कई प्रजातियां बरामद की गईं। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए मछुआरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मोंगला लाया गया है। मोंगला उप जिला मत्स्य अधिकारी जाहिदुल इस्लाम ने बताया कि भारतीय ट्रॉलर मछली पकड़ने के लिए बांग्लादेशी जलक्षेत्र में घुस आए थे। नियमित गश्त के दौरान नौसेना के रडार ने इनको देखा। नौसेना कर्मियों की मौजूदगी का आभास होते ही भारतीय मछुआरों ने ट्रॉलरों के साथ भागने की कोशिश की। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। मोंगला थाना प्रभारी मोहम्मद अनीसुर रहमान ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा: वीजा प्रक्रिया में देरी के कारण 5000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्री काठमांडू में फंसे

एजेंसी

काठमांडू। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वीजा प्रक्रिया में देरी करने के कारण करीब 5000 से अधिक भारतीय श्रद्धालु काठमांडू में फंसे हुए हैं। नेपाल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाले टूरिस्ट और ट्रैकिंग कंपनियों ने चीनी दूतावास से अनुरोध किया है कि वो वीजा प्रक्रिया में देरी किए बिना भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सहज बनाने में मदद करे। भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाले टूर ऑपरेटरों के संगठन एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑपरेटर्स नेपाल के महासचिव प्रदीप पंडित ने बताया कि चीनी दूतावास की तरफ से वीजा प्रक्रिया में विलंब किए जाने के कारण यात्रियों को

काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला तातोपानी नाका और रसुवा नाका दोनों ही इस बार बाढ़, बारिश तथा भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। इस कारण से भी सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। प्रमोद पंडित ने बताया कि इस समय पांच हजार से अधिक भारतीय तीर्थयात्री काठमांडू में ही फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार के माध्यम से तथा स्वयं टूर ऑपरेटर्स भी चीनी दूतावास के अधिकारियों से वीजा प्रक्रिया में देरी नहीं करने के लिए बार-बार आग्रह कर रहे हैं लेकिन चीनी दूतावास की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी चीनी दूतावास से समन्वय का काम किए जाने की जानकारी दी गई है। विदेश सचिव अमृत राय ने बताया कि वो खुद चीनी राजदूत से मिल कर इस समस्या को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए आग्रह कर चुके हैं।

रिश्वत मांगने संबंधि ऑडियो सामने आने के बाद मंत्री राजकुमार गुप्ता ने दिया इस्तीफा

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद आया है जिसमें उनकी कथित तौर पर रिश्वत मांगने की आवाज सुनाई दे रही है। विपक्षी दल गुप्ता के तत्काल इस्तीफे और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। विपक्ष सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगा रहा था।

पद छोड़ने से पहले गुप्ता ने सुबह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। बताया गया है कि प्रधानमंत्री ओली ने राजकुमार गुप्ता को पद छोड़ने का निर्देश दिया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कभी-कभी नहीं खाया हुआ विष का भी असर होता है। उन्होंने लिखा है कि मुझ पर लगे आरोपों की जांच में सहयोग करने के लिए मैने पद से

इस्तीफा दिया है। सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता द्वारा एक सरकारी नियुक्ति और एक ट्रांसफर रुकवाने के बदले 78 लाख रुपये रिश्वत मांगने का ऑडियो पिछले दिनों तेजी से वायरल हुआ। करीब 10 मिनट के इस ऑडियो में मंत्री राजकुमार गुप्ता के द्वारा जिला भूमि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने के लिए 25 लाख रुपये मांगने की बात सामने आ रही है। इसी तरह सामान्य प्रशासन मंत्रालय के एक प्रदेश स्तर के सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए 53 लाख रुपये रिश्वत मांगने की बात भी इस वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही है।

इस्राइल-गाजा संघर्ष विराम पर ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, बोले- अगले हफ्ते समाधान संभव

एजेंसी

गाजा। गाजा में इस्राइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक कोई ठोस समाधान निकल सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोहा में चल रही संघर्षविराम की बातचीत फिलहाल ठहर गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि गाजा पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते तक इसे सुलझा लेंगे। ट्रंप का यह बयान उनके पहले के बयानों की तर्ज पर था, जिनमें उन्होंने मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में काम करने की बात कही थी। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि गाजा में संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक टेबल पर लाया जा सके। हालांकि, दोहा में हो रही संघर्षविराम की बातचीत फिलहाल रुक गई है, लेकिन अमेरिकी पक्ष की कोशिश जारी है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, अमेरिका की टीम कतर, मिस्र और इस्राइल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। बातचीत के केंद्र में गाजा में युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की अनुमति जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। गाजा में लड़ाई अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी है। इस्राइल की मांग है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए, जबकि हमास गाजा में इस्राइली सेना की वापसी की शर्त पर ही समझौते के लिए तैयार है।

न्यूयॉर्क और पांच उपनगरों में तूफान से तबाही, न्यू जर्सी में आपातकाल

एजेंसी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और पांच उपनगरों में तूफान से भारी तबाही हुई है। सब-वे और राजमार्गों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने भारी बारिश की सभी पांच उपनगरों में बाढ़ की चेतावनी जारी की । न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी. मर्फी ने हालात के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार,रात न्यूयॉर्क शहर और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई है। इससे मेट्रो सिस्टम के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं। इसका असर विमानों के आगमन और प्रस्थान पर भी पड़ा। धीमी गति के इस तूफान ने मध्य-अटलांटिक के बड़े हिस्से को पानी-पानी कर दिया। इस वजह से मध्य वर्जीनिया से न्यूयॉर्क शहर तक अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी मेट्रो ट्रेन के डिब्बों में घुस गया। इस दौरान वाहन जलमग्न हो गए। बाढ़ के पानी ने एक पेट्रोल पंप के ईंधन पंपों को तहस-नहस कर दिया। मौसम विज्ञानी जो वेगमैन ने बताया कि कुछ इलाकों में सात इंच तक बारिश हुई। सोमवार देर रात तूफान कमजोर पड़ गया। सोमवार रात राष्ट्रीय मौसम सेवा ने न्यूयॉर्क के सभी पांच उपनगरों में बाढ़ की चेतावनी जारी की। आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए आगाह किया। न्यूयॉर्क शहर के आपातकालीन प्रबंधन विभाग के अनुसार, क्वींस के रिचमंड हिल इलाके में बिजली गुल होने से लगभग 1,000 लोग प्रभावित हुए। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने रात लगभग 11 बजे से पहले बताया कि मैनहट्टन में कई सब-वे स्टेशनों में पानी भर जाने के कारण निलंबित की गई 1, 2 और 3 सब-वे लाइनों पर सेवा बहाल कर दी गई है। एमटीए ने बताया कि स्टेटन आइलैंड रेलवे ने भी दोनों दिशाओं में परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। इस दौरान एमटीए ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आने-जाने वाली हार्लेम और न्यू हेवन रेल लाइनों पर देरी और संभावित निलंबन की चेतावनी दी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच एनजे ट्रांजिट के कई बस मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया है। एनजे ट्रांजिट के अनुसार, न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन और न्यू जर्सी के ट्रेंटन के बीच रेल सेवा अब निर्धारित समय पर चल रही है। उधर, न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी. मर्फी ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के बीच आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। मौसम सेवा ने मध्य न्यू जर्सी और दक्षिण-पूर्वी पेन्सिलवेनिया के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की। मिडलसेक्स काउंटी के प्लेनफील्ड के मेयर ने कहा कि शहर का रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गया है। न्यूयॉर्क की सीमा से लगे उत्तर-पूर्वी बर्गेन काउंटी में सैडल नदी उफान पर है। आपातकालीन प्रबंधन टीम के समन्वयक फिलिप कॉल्विन ने बताया पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर काउंटी के माउंट जॉय में पांच घंटे से भी कम समय में सात इंच से ज्यादा बारिश हुई। न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने बताया कि टैकोनिक स्टेट पार्क-वे में बाढ़ के कारण सभी रास्ते बंद करने पड़े। स्प्रैन ब्रुक पार्क-वे भी बाढ़ के कारण माउंट प्लेजेंट में दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया है।

ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, सोमवार रात को हवाई यात्रा भी बाधित रही। कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाली उड़ानों में तीन घंटे से अधिक की देरी हुई। नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाली उड़ानों में दो घंटे तक की देरी हुई।

रणजीत सागर बांध परियोजना की कालोनी में बिजली बिलो के डिफाल्टरों के बिजली के कनेक्शनों को काटने की मुहित चलाई

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

बांध परियोजना की शाहपुर कंडी टाऊनशिप की कालोनी में बांध परियोजना के बिजली विभाग की ओर से बिजली की चोरी रोकने के साथ अवैध लोगों की ओर से सरकारी आवासों में अवैध रूप से चोरी करके लिए लगाए हुए बिजली के कनेक्शनों व डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान को तेज कर दिया गया है, जिसके तहत आज बांध प्रशासन के बिजली विभाग के एसडीओ सरदार गुरविंदर सिंह, जेई सुशील कुमार, वरिष्ठ टेक्निशियन मंगल सिंह व अन्य टीम की ओर से बिजली के बिलों के डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा तथा पुराने बिलों की अदायगी न होने पर उनके बिजली के कनेक्शन भी काटे। एसडीओ गुरविंदर सिंह अनुसार, उनके मंडल की ओर से शाहपुर कंडी स्थित टाऊनशिप में 25बिजली के बिलों के डिफाल्टरों की सूचि तैयार की है, जिन पर पिछले छह माह से दस हजार रूपए से लेकर साठ हजार रूपए तक बिजली का बिल बकाया बन रहा है, परंतु उक्त डिफाल्टर , बिजली के बिलों का भुगतान नही कर रहे ह, जिसकारण सरकार के राजस्व को हानी हो रही है तथा बिजली का प्रयोग लगातार कर रहे है। हालांकि विभाग की ओर से उक्त डिफाल्टरों को कई वार नोटिस भी दिए गए है, परंतु फिर भी बिजली के बकाए बिल जमा नहीं करवा रहे है, जिसके तहत बिजली मंडल ने कार्रवाइ करते हुए 25 में से 13 डिफाल्टरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए है तथा शेष रहते डिफाल्टरों को एक सप्ताह तक बकाए बिजली के बिल जमा करवाने के लिए अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के शुरू होते ही कुछेक डिफाल्टरो ने अपने बिजली के बिल जमा करवाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है।

बरेली पहुंचीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, कई विभागों की खामियों पर जताई नाराजगी

बरेली । उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी मंगलवार को बरेली दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने किशोर गृह, 300 बेड जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जगह-जगह अव्यवस्थाएं देख उन्होंने संबंधित अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

किशोर गृह में बच्चों से की बात, सुविधाओं का लिया जायजा

निरीक्षण की शुरूआत उपाध्यक्ष ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) से की। यहां उन्होंने अपचारियों से संवाद कर उनके खाने-पीने, कपड़े और रहने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर भी चेक की गई।

शिक्षा विभाग ने डीआरसी वनीत महाजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगल और बीआरसी शाम लाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय नक्की को सम्मानित किया

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंट्री श्रीमती कमलदीप कौर और उप जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंट्री श्री डीजी सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग पंजाब ने नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (एनसीएफ) के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 3 तक प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के लिए पुस्तकें तैयार की हैं। जिसमें जिला पठानकोट के डीआरसी वनीत महाजन राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगल और बीआरसी शाम लाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय नक्की को कक्षा 1 की गणित की पुस्तक तैयार करने में सहयोग दिया गया है। इस संबंध में, शिक्षा सचिव पंजाब अनिंदिता मित्रा के नेतृत्व में चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान, एससीईआरटी पंजाब की निदेशक किरण शर्मा ने पुस्तकें तैयार करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया और उनके कार्य के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री श्रीमती कमलदीप कौर, उप जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री श्री डीजी सिंह, सभी ब्लॉक अधिकारियों, सीएचटी और सभी अध्यापकों ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर डीआरसी वनीत महाजन और बीआरसी शाम लाल ने जिला पठानकोट के अधिकारियों, ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों, सीएचटी और सभी अध्यापकों का धन्यवाद किया और कहा कि वे जिला पठानकोट को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सभी अध्यापकों के सहयोग से इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे और सभी की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

सरकारी ड्यूटी छोड़ निजी अस्पताल में सेवा दे रहे डॉक्टर रंगे हाथों पकड़े गए, कार्रवाई के आदेश

मीरजापुर। जिले में एक बार फिर सरकारी डॉक्टर की ड्यूटी में लापरवाही उजागर हुई है। हलिया ब्लॉक के मुड़पेली न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष कुमार को ड्यूटी समय में निजी अस्पताल में सेवा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह खुलासा तब हुआ जब सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत की जांच के दौरान डिप्टी सीएमओ एवं नोडल अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार सिंह मंगलवार को महुअट गांव स्थित सम्राट हॉस्पिटल पहुंचे।शिकायत अर्चना देवी पत्नी रामचंद्र पाल निवासी मड़वा धनावल ने सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई थी।

सफाई सुपरवाइजर का अपहरण कर बंधक बनाकर वसूली गई फिरौती, चार गिरफ्तार

बांदा। नगर निगम कानपुर में कार्यरत सफाई सुपरवाइजर को विश्वास में लेकर बुलाया गया, फिर उसका अपहरण कर बंधक बनाकर लाखों की फिरौती वसूली गई। इस सनसनीखेज वारदात का चौंकाने वाला खुलासा चिल्ला पुलिस ने करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी, जेवरात, अवैध हथियार व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि पीड़ित दयाराम पुत्र गंगादीन, निवासी पुराना कानपुर, नगर निगम कानपुर में सफाई सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है। दयाराम किराये पर जिस मकान में रहता था, उसी में शिवगोविंद सोनी उर्फ पिंटू सोनी अपनी पत्नी मोना देवी के साथ रहता था। उसी दौरान दयाराम की मोना देवी से जान-पहचान हो गई थी। कुछ समय बाद पिंटू सोनी अपनी पत्नी के साथ वह मकान छोड़कर फतेहपुर आ गया।

11 जुलाई 2025 को मोना देवी ने दयाराम को फोन कर फतेहपुर बुलाया, यह कहकर कि "चाचा, कुछ जरूरी बात करनी है।" विश्वासवश जब दयाराम फतेहपुर पहुंचा, तो लखनऊ बाईपास के पास पिंटू सोनी, उसकी पत्नी मोना देवी, उसका भाई बजरंगी सोनी तथा दो अन्य व्यक्ति एक ऑटो में पहुंचे और जबरन दयाराम का अपहरण कर कस्बा चिल्ला, जनपद बांदा ले गए। वहां उसे एक घर में बंधक बनाकर मारपीट की गई और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।

दिल्ली में जल्द आनी चाहिए वैट एमनेस्टी स्कीम - सीटीआई

दिव्य दिल्ली : देश में 2017 में GST लागू हुआ है और उससे पहले VAT (वैल्यू एडेड टैक्स) लगता था, आज भी दिल्ली में वैट प्रणाली के 3 लाख से ज्यादा केस फंसे हुए हैं,इसको लेकर आज दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में के नेतृत्व में दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली की GST कमिश्नर नंदिनी पालिवाल से मुलाकात की । सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में 8 साल से 3 लाख से ज्यादा व्यापारियों के वैट प्रणाली के केस फंसे हुए हैं, बहुत सारे व्यापारियों के कोर्ट में केस चल रहे हैं इसलिए कमिश्नर से एक वैट एमनेस्टी स्कीम लाने का अनुरोध किया है जिसके अंतर्गत व्यापारियों से एक निश्चित अमाउंट वसूलकर पुराने केस खत्म किए जाएं,सीटीआई का अनुमान है कि करीब 85 हजार करोड़ रूपए के टैक्स अमाउंट के ये केस हैं और सरकार अगर एक एमनेस्टी स्कीम लाती है तो सरकार को करीब 10 -15 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा,कुछ राज्यों में पहले से ही वैट एमनेस्टी स्कीम आ चुकी है,इस पर जीएसटी कमिश्नर नंदिनी पालिवाल ने कहा कि दिल्ली में एक वैट एमनेस्टी स्कीम पर काम चल रहा है और जल्द ही लागू होने की संभावना है।

सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों को किया जाए सम्मानितमीटिंग में शामिल उअ बिमल जैन और उअ राकेश गुप्ता ने कहा कि जो लोग सरकार को अच्छा GST देते हैं उनको सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाए ,सरकार को हर ट्रेड और आइटम्स के हिसाब से ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों को समय समय पर सम्मानित किया जाए जिससे कि दूसरे व्यापारी भी प्रोत्साहित होंगे

सीलमपुर पुलिस आयुक्त के अंतर्गत थाना वेलकम के साथ नागरिक सुरक्षा समिति की टीम कर रही शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा और यातायात मार्ग ड्यूटी

दिव्य दिल्ली : जावेद खान संवाददाता उत्तर पुर्वी दिल्ली सीलमपुर पुलिस उपायुक्त के अंतर्गत थाना वेलकम पुलिस की टीम के साथ एवं थाना जफराबाद सीलमपुर थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ नागरिक सुरक्षा समिति की टीम शिव भक्तों की सेवा एवं यातायात मार्ग को खुलवाने एवं उनकी सेवा में समर्पित तत्पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हसीन अहमद चीफ कनवीनर ने पत्रकारों से बताया है कि हमारी नागरिक सुरक्षा समिति की टीम हर त्यौहारों और सर्व समाज के लिए कार्य करते है जो बिना किसी स्वार्थ अपना योगदान एवं समय दिन रात ड्यूटी कर के देते हैं नागरिक सुरक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है। जिससे समाज की सेवा से आपसी सौहार्द मानवता मोहब्बत को बढ़ावा मिल सके और जो एक मजबूत और एकजुट समुदाय बनाने में मदद मिल सके जिससे सर्व धर्म सर्व समाज एक रहे और आपसी मत भेद नहीं रहे। हसीन अहमद चीफ कनवीनर ने आगे कहा कि हिन्दू से पूछिए न मुसलमाँ से पूछिए इंसानियत का गम किसी इंसाँ से पूछिए और सात संदूकों में भर कर दफ़्न कर दो नफरतें आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है । भारत में एकजुट होकर रहो जिससे नफरत नहीं पनप सके। हसीन अहमद चीफ कनवीनर से पत्रकार ने पूछा नफरत क्या है तो उन्होंने कहा कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए मैं तो हर वक़्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ . सारे जग को जुड़ने में लगा हु। नागरिक सुरक्षा समिति हर त्यौहारों पर अपनी टीम की भागीदारी को दशार्ती हैं और हर वक्त हर समय हर घटना पर पुलिस के साथ मौजूद होती हैं। कांवड़ियों की सेवा में ड्यूटी में मदन लाल कश्यप चीफ कनवीनर और दीपक कुमार मोहम्मद नसीम डिप्टी कनवीनर महेश जिंदल डिप्टी कनवीनर शाहिद खान नौशाद अरशद खान इमरान चौधरी पत्रकार एवं महिला टीम पायल पिंकी पूनम राधिका गौतम एवं नागरिक सुरक्षा समिति की टीम अन्य टीम समाज सेवा टीम सहित अपने कर्तव्य निभाते हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। जिससे ट्रैफिक यातायात में किसी भी तरह की बाधा नहीं हो और शिव भक्त कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हर वक्त नागरिक सुरक्षा समिति सेवा में समर्पित है।

अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थित मजबूत करने को पहली बार बकरी पालन योजना

प्रयागराज। योगी सरकार अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पहली बार पशुधन विभाग के माध्यम से बकरी पालन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के गरीब, महिला,विधवा और दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी। इस कारोबार को शुरू करने के लिए सरकार 90 प्रतिशत का अनुदान देगी और दस प्रतिशत लाभार्थी को खर्च करना होगा। यह जानकारी प्रयागराज मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. शिव नाथ यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि पशुधन एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से योगी सरकार ने पहली बार अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरू की है। ऐसी योजना पहली बार शुरू की गई है। बकरी पालन की इस योजना की लागत कुल 60 हजार निर्धारित की गई है। जिसमें लाभार्थी को 10 प्रतिशत स्वयं खर्च करना होगा।

पांच बकरी व एक बकरा खरीदकर शुरू करें

डॉ. शिवनाथ यादव ने बताया कि लाभार्थी को कुल पांच बकरी और एक बकरा खरीदना होगा। एक बकरी की कीमत 9 हजार और बकरे की कीमत 10 हजार निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं खर्च करना पड़ेगा।

कहां और कैसे करें आवेदन

डॉ. शिवनाथ यादव ने बताया कि पशुपालन विभाग इस योजना को शुरू करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में ग्राम समिति बनाई है, जिसका मुख्य अधिकारी डिप्टी सीबीओ को बनाया गया है। लाभ लेने के लिए सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास आवेदन करना होगा। ग्राम प्रधान उसे आगे बढ़ाते हुए डिप्टी सीबीओ के पास भेजेगा।

ये है शर्तें

बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए बकरी पालन का अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड तथा तीन वर्ष के लिए बकरी पालन का कारोबार करने के लिए शपथ पत्र देना होगा।

यश दयाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

प्रयागराज । क्रिकेटर यश दयाल को यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर तलब किया है।

यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने बताया, "जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच में मामले पर सुनवाई हुई। हमने एफआईआर को चुनौती दी है, जो इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया गया।" अधिवक्ता ने कहा, "कोर्ट के समक्ष लंबी बहस चली, जिसमें सभी तथ्य सामने रखे गए। कोर्ट ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।"

10 वर्षों से कायम है एंग्री मैन का खिताब

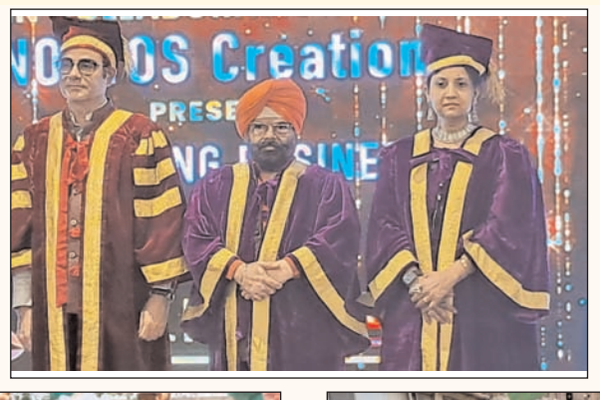

दिव्य दिल्ली : क्या आप जानते हैं 10 वर्षों से एक ही इंसान एंग्री मैन के खिताब पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। जबकि यह खिताब पाने के लिए कोई भी अभी तक आस-पास भी नहीं पहुंच पाया। 2015 में परमजीत सिंह पम्मा को बीबीसी सहित सोशल मीडिया ने एंग्री मैन का खिताब दिया। जिसे परमजीत सिंह पम्मा ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अभी तक उसे खिताब पर कब्जा बनाए हुए हैं। पम्मा महंगाई, भट्टाचार्य,आतंकवाद, बच्चों की स्कूल की फीस का मामला हो या ऑनलाइन गमों का यहां तक के व्यापारियों का भी कोई मुद्दा हूं 31 वर्षों से इसी प्रकार धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं कभी वह जंतर मंतर पर तो कभी पाकिस्तान दूतावास के सामने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और सरकार व प्रशासन तक आम लोगों की आवाज पहुंचते हैं।पम्मा का कद का चाहे छोटा है। मगर उनकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि देश, विदेश का मीडिया उनके धरने, प्रदर्शनों को प्रमुख रूप से छपने पर मजबूर हो जाता है। पम्मा ने एक गैर राजनीतिक नेशनल अकाली दल नाम से से एक संस्था बना रखी है जिसके जरिए वह सामाजिक कार्य करते हैं। जबकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार के व्यापारियों की संस्था फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन पर नियुक्त है।पम्मा का कहना है कि जब भी आम आदमी को परेशानी होती है तब ही उनको गुस्सा आता है। लोगों की भलाई के लिए ज्यादा गुस्सा करने के कारण उनकी तबियत कई बार खराब हो चुकी है तथा वे हार्ट के मरीज बन चुके हैं और उनका आपरेशन भी हो चुका है।

दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ने के बाद पम्मा ने महंगी प्याज खरीद कर सस्ते में बेचीं तथा टीवी पर अश्लीलता के खिलाफ प्रदर्शन में उन्होंने टीवी को आग लगाई। इस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर वे प्रदर्शन करते ही रहते हैं। उनको जानने वाले लोगों का कहना है कि वे एक अच्छे इंसान है और लोगों की भलाई के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।पम्मा के कार्यों पर मशहूर गायको ने 10 गाने गाए साथ ही उनके जीवन पर कहीं डॉक्यूमेंट्री भी बन चुके हैं।

बिग बॉस फेम

कशिश कपूर

ने घर पर हुई चोरी के बारे में की बात, वीडियो में छलका एक्ट्रेस का दर्द

बिग बॉस फेम कशिश कपूर हाल ही में चोरी की घटना से लोगों के बाच चर्चा में बनी हुई हैं. सामने आ रहे खबर के मुताबिक कशिश के घर से उनके कुक ने तकरीबन 7 लाख रुपए चोरी किए हैं. 13 जुलाई को इस खबर का खुलासा हुआ तो सभी काफी हैरान थे, हालांकि ये मामला कुछ दिन पहले का है, जिसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हिंट दिया था. फिलहाल इस मामले को पुलिस देख रही है, लेकिन इसी बीच कशिश ने खुद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उस दिन की घटना बताते हुए काफी इमोशनल नजर आ रही हैं.कशिश कपूर ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपने कुक सचिन कुमार चौधरी पर चोरी का इल्जाम लगाया है. कशिश ने बताया कि वो अपने पैरंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों को भी चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था. कशिश ने बताया कि उन्होंने अपने घर में 7 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, जिसे वो अपनी मां के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली थीं. हालांकि, इससे पहले ही पैसे चोरी हो गए थे.

7 लाख रुपए हो गए चोरी

कशिश काम की वजह से सिंगापुर जाने वाली थीं, इसके एक दिन पहले ही उन्होंने अपने लॉकर में रखे 7 लाख अपनी मां को भेजने वाली थीं. हालांकि, जब वो पैसे लेने गईं, तो वहां मौजूद लिफाफा बिल्कुल खाली था. जिसके बाद से वो शॉक्ड हो गई , जिसके बाद उन्हें अपने कुक सचिन पर शक हुआ, जो तुरंत ही उनके घर से गया था. वो सचिन के पीछे गईं और उसे लिफ्ट में रोक लिया और उसे वापस घर आने को कहने लगी.

कशिश का पकड़ लिया हाथ

सचिन जब उनके घर में वापस आया तो कशिश ने उससे उसकी जेब दिखाने को कहा, जिसके काफी वक्त के बाद उसके पॉकेट से 50 हजार रुपए निकले. हालांकि, ये देखते ही कशिश ने फोन उठाने की कोशिश की लेकिन इतनी देर में सचिन ने उनके दोनों हाथ पकड़े और दीवार के सहारे उन्हें धकेला. इसके बाद उसने कशिश को किसी को भी इस बारे में नहीं बताने की बात कही. हालांकि, उस वक्त उन्होंने सेफ होने के लिए सचिन को तुरंत घर से जाने को कह दिया.

पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

कशिश ने कहा, जैसे ही कुक घर से निकला मैंने गार्ड को फोन किया, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो तुरंत लगा नहीं. जब तक गार्ड को फोन लगा तब तक सचिन बिल्डिंग से बाहर जा चुका था. हालांकि, 20वें मंजिल से कशिश सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आईं और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद से सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, काफी लंबा वक्त पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद पुलिस ने कशिश को बताया कि वो पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं दे सकते हैं.

26 साल की उम्र में फेमस इन्फ्लुएंसर और मॉडल सैन रेचल ने की खुदकुशी, छोड़ गईं सुसाइड नोट

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल सैन रेचल की सुसाइड की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सैन ने कई सारी गोलियां एक साथ खा ली जिसके बाद से उन्हें दो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें मृत बता दिया. हालांकि, अभी तक सुसाइड की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि सैन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थीं. उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें सैन ने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया है.सैन रेचल पुडुचेरी की फेमस मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बनाई, उनका असल नाम शंकर प्रिया है. सैन पिछले काफी समय से किडनी की परेशानी से भी जुझ रही थी, जिसका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि सैन काफी ज्यादा कर्ज में चली गई थीं, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है. सैन ने पिछले साल ही शादी रचाई थी, फिलहाल इस मामले में जांच चल रहा है, जिसमें पता चला है कि उन्होंने अपने गहने भी गिरवी रखे थे.

हुआ था काफी नुकसान

26 साल की सैन रेचल मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुकी थीं. उन्होंने साल 2020-2021 में मिस पांडिचेरी, 2019 में मिस डार्क क्वीन तमिलनाडु और उसी साल मिस बेस्ट एटीट्यूड सहित कई खिताब जीता था. साथ ही साथ रेचल ने ब्लैक ब्यूटी कैटेगरी में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था.

मिला है सुसाइड नोट

रेचल ने हुए नुकसान के लिए अपने पिता से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की जिम्मेदारियों का कहकर मदद से इनकार कर दिया था.

उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. रेचल ने बीपी की कई सारी गोलियां खा ली थी, जिसके बाद से उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद से उन्हें जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई.

मुझे किसी लैंग्वेज से... भाषा विवाद पर आर माधवन ने किया रिएक्ट, कह दी बड़ी बात

बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम करने वाले एक्टर आर माधवन ने भारतीय ऑडियंस का दिल जीता है. हाल ही में उनकी फिल्म आप जैसा कोई नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. फातिमा सना शेख के साथ आई उनकी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में एक्टर ने हालिया इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म का प्रमोशन भी किया और उन्होंने मौजूदा समय में चल रहे मुद्दों के बारे में भी बातें की. उन्होंने मौजूदा समय में देश में चल रहे भाषा विवाद पर भी प्रकाश डाला.

आर माधवन से हाल ही में इस बारे में बात करते हुए कहा- 'नहीं, मैंने कभी तक ऐसा एक्सपीरियंस्ड नहीं किया है. मैं तमिल बोलता हूं. मैं हिंदी भी बोलता हूं. मैंने कोल्हापुर में पढ़ाई की है तो मैंने मराठी भी सीखी है. लेकिन मुझे कभी भी किसी भी भाषा से कोई समस्या नहीं है. जो भाषा मुझे आती है उससे भी मुझे नहीं दिक्कत और जो भाषा मुझे नहीं आती है उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है.' आर माधवन दरअसल अलग-अलग जगहों पर रहे हैं इसलिए उन्हें कई सारी भाषाएं आती हैं. उन्हें फिल्मों में भी इसका बहुत फायदा मिला है.

अजय देवगन ने क्या कहा ?

अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ. इस दौरान उनसे भी भाषा विवाद को लेकर सवाल किए गए. उन्होंने भी इस सवाल पर रिएक्ट किया. अजय देवगन ने कहा कि भाषा को लेकर देशभर में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आता माझी सटकली. अजय के इस रिएक्शन के बाद सभी उनके ह्यूमर पर हंसते नजर आए.

साल 2025 में आर माधवन की तगड़ी प्लानिंग

आर माधवन की बात करें तो साल 2025 में वे अपने फैंस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं. पहले ही उनकी फिल्म टेस्ट और केसरी चैप्टर 2 आ चुकी है और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्म आप जैसा कोई भी रिलीज हो चुकी है. इन फिल्मों के अलावा आर माधवन एक साउथ फिल्म का भी हिस्सा हैं. और वे धुरंधर फिल्म के साथ भी जुड़ गए हैं जिसका इंतजार फैंस को बेसब्री से है. मतबल 2025 में आर माधवन की ओटीटी से लेकर बॉलीवुड और साउथ के बॉक्स ऑफिस पर भी छाने की तैयारी की हुई है.

इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं यूट्यूबर

आशीष चंचलानी

एक तस्वीर ने मचाई हलचल

आशीष चंचलानी ने यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद उनके तमाम चाहने वाले उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं. साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि वो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में हैं.12 जुलाई को

आशीष ने इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवराम के साथ एक फोटो शेयर की है. तस्वीर में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. एली ने अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता भी ले रखा है. इस फोटो को शेयर करते हुए आशीष ने कैप्शन में लिखा, आखिरकार. आगे उन्होंने एक हार्ट इमोजी भी ड्रॉप की है.

मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन

इस तस्वीर और एक शब्द के कैप्शन से लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. फैंस के साथ-साथ इस पोस्ट पर कई सितारों के भी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और सभी दोनों को बधाई दे रहे हैं. मुनव्वर फारूकी ने लिखा, फिल्म के प्रीमियर में जाने के फायदे. आगे उन्होंने एक हार्ट इमोजी भी शेयर की है.

मुनव्वर अपने इस कमेंट के जरिए किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. एक यूजर ने लिखा, अपना आशु शादी कर रहा है फाइनली.एक और शख्स ने लिखा, मुबारक भाई.

क्या प्रैंक कर रहे हैं आशीष चंचलानी

जहां एक तरफ लोग दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि ये प्रैंक होगा. आरजे महवश को भी ऐसा ही लगता है. उन्होंने कमेंट किया, मैं 'आखिरकार' के बाद के सेंटेंस का इंतजार कर रही हूं. आगे उन्होंने पंच मारने की इमोजी ड्रॉप की है और कहा कि अगर प्रैंक हुआ तो पंच मारूंगी.एक यूजर ने लिखा, मैं नहीं मानता प्रैंक होगा पक्का. एक दूसरे ने कमेंट किया, कह दो ये झूठ है, प्रैंक हा न ? अब आशीष और एली सच में डेट कर रहे हैं या फिर ये प्रैंक है ? इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है.

भाषा विवाद की आंधी के बीच विख्यात मराठी कवि संत तुकाराम की फिल्म हिंदी में रिलीज

दिव्य दिल्ली : अजीब विडंबना है कि इन दिनों जब महाराष्ट्र सहित देश के कई शहरों में भाषा विवाद चरम सीमा पर है तो ऐसे में विश्व विख्यात कवि संत तुकाराम की जीवनी पर फिल्म संत तुकाराम हिंदी में बनाई गई ,और फिल्म के यंग निर्देशक आदित्य ओम ने अपनी इस बायोपिक फिल्म को महाराष्ट्र के सभी शहरों में यह फिल्म सिर्फ हिंदी में 18 जुलाई को रिलीज होगी। नई दिल्ली के बिग ओडियन मल्टीप्लेक्स में अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने आए आदित्य ओम इस खास मौके पर अनेक रंगकर्मी , साहित्यकार , लेखक, और वरिष्ठ पत्रकार , उच्च अधिकारी भी फिल्म की लीड जोड़ी मराठी फिल्मों के सुपर स्टार सुबोध भावे और एक्ट्रेस शीना चौहान , शिवा सूर्यवंशी, शीशर शर्मा , विख्यात रंगकर्मी अरविंद गौड़ आदि भी निर्देशक आदित्य की इस फिल्म को प्रमोट करने की मुहिम में शामिल हुए।इस फिल्म के युवा निर्देशक , लेखक आदित्य ओम ने यहां मौजूद मीडिया के सवालों की बौछार के बीच बताया 17 वी सदी के संत, समाज सुधारक संत तुकाराम पर फिल्म बनाने का जुनून मैंने अपने अंदर बरसो से समा रखा था, कई वर्ष की शोध और अनेक मराठी लेखकों से मिलने और संत तुकाराम पर बनी पुरानी फिल्मों से प्रेरणा लेकर मैने इस प्रोजेक्ट पर जब काम पर शुरू किया तो मुझे धमकियां तक मिली लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जब मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार सुबोध भावे ने इस फिल्म में संत तुकाराम के लीड किरदार निभाने के लिए हामी भर दी तो मेरी एनर्जी कई गुना बढ़ गई।फिल्म के लीड किरदार सुबोध भावे जो मराठी की 90 से ज्यादा फिल्में कर चुके है और इन फिल्मों में से कई फिल्मों बायोपिक है यह सभी फिल्मे बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, सुबोध भावे ने मीडिया कर्मियों को बताया इस किरदार के लिए मैने बहुत होम वर्क किया संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़े कई ग्रन्थ पढ़े इस किरदार को जीवंत करने के लिए मैं संत तुकाराम के अनेकों भक्तों तक से मिला। भावे कहते है एक मराठी संत पर बनी यह फिल्म भाषा के नाम पर विवादों को जन्म देने और भाषा पर राजनीति करने वालो के नाम पर तमाचा है ,विख्यात मराठी संत पर फिल्म को मराठी की बजाय हिंदी में बनाया जाना साबित करता है कोई भी भाषा हमे टकराव नहीं प्रेम का संदेश बताती है।

फैक्ट्री मालिकों ने उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा से की मुलाकात

दिव्य दिल्ली : विभिन्न क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों ने दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। इसमें अत्यधिक सर्कल रेट और औद्योगिक क्षेत्रों के फ्री होल्ड, न्यूनतम मजदूरी और बिजली के ज्यादा रेट पर चर्चा हुई। चैंबर ऑफ ट्रेड इंड इंडस्ट्री (CTI) के नेतृत्व में हुई मीटिंग में उद्यमियों ने अपनी परेशानियां साझा की। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि मीटिंग के दौरान उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा ने आश्वस्त किया है कि दिल्ली सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री होल्ड करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, एक-एक करके सभी इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड किया जाएगा। साथ ही जहां भी सर्कल रेट वास्तविक मूल्य से ज्यादा हैं, उन्हें घटाया जाएगा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन पर काम जारी है, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी होंगे। मंत्री को CTI ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मीटिंग में राजीव गोयल, अशोक गोयल, पवन गर्ग, कैलाश मंगला, राहुल अदलखा, राजेश खन्ना और नईम राजा आदि उपस्थित रहे।उळकने सौंपा मांग पत्र बवाना, भोरगढ, झिलमिल, बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाए। दिल्ली में नरेला समेत अनेक बहुत सारी जगहों पर सर्कल रेट की विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक किया जाए।पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में मिनिमम वेजेज बहुत ज्यादा है, जिससे फैक्ट्री मालिकों की लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, जिसे ठीक किया जाए। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की दरें, दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, उनको तर्क संगत किया जाए। राजधानी में हजारों फैक्ट्रियां किराए पर चलती हैं। किराएदार या अन्य फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उनको हर बार उढउउ से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जबकि GST में एड्रेस बदलने पर भी GST नंबर एक ही रहता है। ये ठीक किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए। DSIIDC, MCD, लेबर, बिजली, पर्यावरण, नाप-तौल विभाग, फायर विभाग आदि अनेक विभागों से फैक्ट्री मालिकों को अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे सिंगल विडियो सिस्टम में लाया जाए।दिल्ली सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा की है। इसमें दुकानदारों के साथ फैक्ट्री मालिकों को भी शामिल किया जाए।

न्यूज फ्लैश

नीति महाजन बनीं इनर व्हील क्लब की नई अध्यक्ष ,2025-26 के लिए निर्वाचित हुई

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर इनर व्हील क्लब का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आज वड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के कार्यक्रम मे क्लब की नई अध्यक्षा नीति महाजन को सर्व समिति से चुना गया ' क्लब की पहली इस वैठक मे नीति महाजन ने अपनी बुद्धिमता से पहली वार 35 नए सदस्यों को अपने साथ जोड़कर क्लब मे नया इतिहास रचा' यह जानकारी आज वैठक के वाद क्लब की नई अध्यक्षा नीति महाजन ने देते हुए वताया कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उस पर अच्छा उतरने का प्रयास करूंगी' सबको साथ लेकर चलना मेरी प्राथमिकता होगी ' महाजन ने वताया कि इस अवसर पर कल्ब ने एक गरीब मजदूर को हीरो साइकिल दान की जिससे वह काम पर आसानी से जा सके।डोनेट, डोंट डंप" प्रोजेक्ट के तहत हमने मजदूर महिलाओं को कपड़े, आटा, तेल, चावल, दाल, मसाले और हैंडबैग दान किए। इतना ही नही कार्यक्रम में खेलों का आयोजन हुआ और 15 विजेताओं को पुरस्कार मिले। क्लब ने इस अवसर पर केक काटकर आज इस कार्यक्रम का जश्न मनाया गया ' इस अवसर पर क्लब के पुराने चार्टर सदस्यों को उपहार देकर इस कार्यक्रम मे सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम मे कल्ब की अध्यक्षा नीति महाजन ने अपनी तरफ से सभी सदस्यों को प्यार भरे उपहार भी दिए ' इस अवसर पर क्लब नई अध्यक्षा नीति महाजन ने कार्य करणी का भी गठन किया गया ' जिसमे नई टीम 2025 -26 के लिए सचिवः सुरूचि महाजन उपाध्यक्षः रजता महाजन व संपादकः रिधिमा महाजन मनोनीत की गईं ' सभी लोगों ने इस अवसर पर नीति महाजन को क्लब की अध्यक्षा बनने पर मुबारकबाद भी दी '

राष्ट्रीय राजमार्ग दुनेरा बाजार में रोजाना लग रहा भारी ट्रैफि क जाम

दिव्य दिल्ली : पठानकोट(करूनीत रंधावा)

पठानकोट-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ब्लॉक धार कलां के अंतर्गत पंजाब- हिमाचल प्रदेश सीमा के निकट बसा गांव दुनेरा जो मणिमहेश, ब्रामणी माता, तीसा, चम्बा, डलहौजी आदि आने-जाने वाले गाँव दुनेरा बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन है। दुनेरा के बाजार (जिसके बीच से ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है) में रोजाना भारी ट्रैफि क कारण जाम लगा रहता है। दुनेरा बाजार में अक्सर वाहन चालक चाय, नाश्ता और आम पापड़ खरीदने के लिए रुकते हैं। लेकिन वाहन चालक बाजार में बेतरतीब ढंग से अपने वाहन पार्क कर देते हैं। जिससे आने-जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है और कई लोग काफी देर तक ट्रैफि क जाम में फँसे रहते हैं। आजकल श्रद्धालु भगवान शिव जी के पवित्र तीर्थस्थल पर भी जा रहे हैं जिसके कारण इस सड़क पर भारी ट्रैफि क जाम लग रहा है। वाहन चालक इस ट्रैफि क जाम में फँसी एक एम्बुलेंस के सायरन को अनदेखा करते नजर आए। जिसमें मरीज काफी परेशान दिखे। बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण लोग खाने-पीने का आनंद लेते देखे गए। लोगों की माँग है कि दुनेरा बाजार में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और ट्रैफि क जाम न लगे, इसके लिए स्थायी पुलिस बल तैनात किया जाए।

शाहपुर कंडी के सरकारी सीसे माडल स्कूल में रेबिज के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

शाहपुर कंडी टाउनशिप के सरकारी मॉडल स्कूल में पशुपालन विभाग, पंजाब की ओर से रेविज के प्रति अवेयर करने के लिए , भाषण प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल की प्रिंसींपल अरूणा कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रतियोगिता में आधुनिक समाज में जानवरों की भूमिका, और कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ पर आधारित था। इस प्रतियोगिता में तीस स्टुडैंटस ने भाग लिया और अपने भाषण कौशल का प्रदर्शन किया। विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें प्रथम स्थान पर खुशबू, दूसरे स्थान पर सिया शर्मा और तृतीय स्थान पर शिवांगी रही। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लेक्चरर राजीव गुप्ता ने किया, जिन्होंने अपनी कुशल मेजबानी से कार्यक्रम को रोचक बनाया। जागरूकता सैमिनार में डॉ. धवन, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉ. समेश, डॉ. यामी, डॉ. साक्षी, डॉ. कविता, डॉ. अंकुर, प्रिंसिपल अरुणा कुमारी मनप्रीत सिंह , राजीव महाजन व अन्य ने अपने अनुभवों को शेयर किया। जतिंदर बावा, सीमा शर्मा और सीमा प्राशर ने जज की भूमिका निभाई और प्रतिभागियों के भाषण कौशल का मूल्यांकन किया। पशु चिकित्सक डॉ. धवन ने कहा, रेबीज एक गंभीर बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। हमें इसके प्रति जागरूक रहने और बचाव के उपाय करने की आवश्यकता है।

वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट 2025 का भव्य समापन, उभरते कलाकारों को मिला मंच

दिव्य दिल्ली : एस जी एंटरटेनमेंट द्वारा वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट 2025 का दिल्ली के सत्यवती कॉलेज ऑडिटोरियम मे, भव्य समापन समारोह हुआ, इस कार्यक्रम को आयोजित मिस्टर सनी ने किया, सनी खुद बहुत ही अच्छे कलाकार हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में उनकी खुद की एक पहचान है, सह आयोजक ट्रिब्यूट फॉर यूथ (एनजीओ) के महासचिव विनोद गुप्ता और फ्यूचर फाउंडेशन (एनजीओ) के महासचिव अशोक कुमार जी पुरी टीम ने मिलकर कार्यक्रम को सफलता दिलाई इस कार्यक्रम का मैनेजमेंट रिद्धि सिद्धि एडवरटाइजिंग श्री विनय ढींगरा ने बहुत ही खुबसूरती से कार्यक्रम को मैनेज किया, संगीत प्रबंधन हरप्रीत कौर मस्तानी और प्रिंस वाधवा टीम ने किया इसमें दिल्ली एनसीआर व अन्य राज्यों से आयी तमाम प्रतिभाओ ने अपना-अपना जलवा बिखेरा। वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट 2025 के विजेता सितारे प्रथम अलविना कुरेशी, द्वितीय प्रत्यक्ष कलाया, तृतीय डॉ.हरप्रीत कौर मस्तानी, रहे जिन्हों वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट का खिताब जीता , कार्यक्रम के मुख्य जज वॉइस ऑफ इंडिया फेम दीपक राणा, इंडियन आइडल फेम मानसी सिसौदिया और बॉलीवुड सिंगर माही नैय्यर रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूनम भारद्वाज विधायक वजीरपुर विधानसभा,पारस भाई गुरु धार्मिक नेता एवं गायक), संत बुच्ची धाम रतन शफाखाना संत प्रीतपाल सिंह चन्ना सुभाशीष गुरुजीपीठाधीश्वर (बालाजी ज्योतिष पीठ), गौरव बिदुड़ी (विश्व मुक्केबाजी चैंपियन), सेलिब्रिटी सिंगर रमेश अग्रवाल और सिमता कौशिक निगम पार्षद उपस्थित रहे वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट की टीम ने बहुत मेहनत की डायरेक्टर पंकज बमोत्रा जी,अध्यक्ष संजय कुमार झा ,टीम ऑर्गेनाइजर शिल्पा नैय्यर अकाउंटेंट हिमांशु सलारिया, प्रोफेशनल सिंगर अमित बंगा जी,सिंगर सनी भी कहा हमारी पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की और सभी म्यूजिक लवर्स को दिल से धन्यवाद करा और वॉयस ऑफ सिटी टैलेंट हंट सीजन 2 मैं आप सभी पब्लिक का आशीर्वाद चाहिए जिससे हम अच्छे अच्छे कलाकार को अच्छा मंच प्रदान कर सकें

गांव में सड़क नहीं, मरीज को पालकी पर उठाकर 13 किमी पैदल ले जाना पड़ा

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर हिमाचल प्रदेश की भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जंदरोग के गांव चक्की की हालत आजादी के 75 साल बादभी आज बेहद दयनीय बनी हुई है। इस गांव में न तो सड़क है न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बीमार व्यक्तियों को पालकी मे उठाकर पहाड़ों के खतरनाक और फिसलन भरे रास्तों से कई किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ता है। हाल ही की घटना में एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर गांववासियों ने उसे पालकी पर बाँधकर चार-छह लोगों की मदद से जंगल और पहाड़ी रास्तों से नीचे अस्पताल तक पहुँचाया। बारिश के मौसम में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है ' इस गांव की जनसंख्या लगभग 700-800 है ।जिसमें प्रभावित गाँव श्रृंखला जिसमें ठेहड़ा,चिहुण, कुट. बातलीबेई, आहन, गोठ, रंथभोंरा, आरुफेरा, चक्की आदि गांव हैं लेकिन आज तक इन गावों को पक्की सड़क, स्वास्थ्य केंद्र या आपातकालीन सेवा की सुविधा नहीं मिल सकी है।इस मामले मे क्षेत्र वासियो का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन को शिकायत दी है लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है।

बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने अपने रोजगार की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन व धरना दिया

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

शाहपुर कंडी में डैमज प्रशासन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर बैराज बांध की बनी हुई झील से विस्थापित हुए परिवारों ने अपने रोजगार व अन्य मुआवजों की मांग को लेकर 106वें दिन भी अपनी भूख हडताल व रोष प्रदर्शन कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी व थीन डैम वर्कर्ज यूनियन के प्रधान जसवंत सिंह संधू की अध्यक्षता में जारी रखा। आज 106वें दिन पर अवतार सिंह जैनी, दर्शन सिंह जैनी सिंह जैनी, धीरज कुमार शाहपुर कंडी, मेहर चंद कोट व मेजरू शाहपुर कंडी ने अपनी भूख हडताल जारी रखी। विस्थापित परिवारों व कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि , बैराज बांध प्रशासन व पंजाब सरकार ने बैराज बांध की बनी हुई झील के लिए उनके कई गांवों से उनकी भूमि व आवासों को अधिगृहित किया है, जिसके लिए आर एंड आर पालिसी अनुसार, पुनार्वास मुआवजा व रोजगार देने का प्रावधान है, परंतु बैराज बांध प्रशासन ने अपनी मनमानी करके, गलत नियमों को बना कर उनके साथ धोखा किया है, जिसकारण उनके हजारों प्रभावित परिवारों को रोजगार हासिल करने में समस्या बन रही है। । रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि पुरानी आर एंड आर पालिसी को बहाल किया जाए , उनका बनता रोजगार दिया जाए व पुनार्वास मुआवजा दिया जाए । इसके साथ ही विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीध्र ही उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह तीस जुलाई को फिर से चीफ इंजीनिया कार्यालय का घेराव व भारी रोष प्रदर्शन करेगें। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी , कर्मचारी नेता जसवंत संधू, रोहित कुमार, सुरजीत सिंह, रविंद्र बाबा, रजत बलोतरा, जसविंदर सिंह, विनोद शर्मा, आदर्श वाला, विनोद कुमारी, बीतू देवी, यशोदरा देवी,रमेश कुमार , राहुल शर्मा, कुलदीप शर्मा, हरनाम सिंह , अंशू शर्मा, हनी कुमार व अन्य उपस्थित थे।

तुगलकी फरमानों को निरस्त करें विद्युत बोर्ड प्रबंधन वर्ग

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपु)

विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम नूरपुर की टीम डोर टू डोर अभियान के तहत आज गांव टटल, जोंटा नूरपुर क्षेत्र के विद्युत पेंशनरो को घर-घर जाकर फोरम की सदस्यता प्रदान की। इस अवसर पर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल ने कहा कि कर्मचारियों, पेंशनरों,इंजीनियरों , आऊटसोर्स कर्मचारियों के ज्वाइंट फ्रंट ने कर्मचारियों, पेंशनरो की मांग को लेकर 11 फरवरी 2025 से जिले बार महापंचायत करने की शुरूआत जिला हमीरपुर से की थी। इसके बाद उना ,चंबा बिलासपुर, रामपुर, सिरमौर और दिनांक 9 जुलाई 2025 को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में महापंचायत का विशाल आयोजन किया जिसमें जिला कांगड़ा से विद्युत परिवार से करीब 5000 सदस्यों ने भाग लिया। इस विशाल रैली को देखकर बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने शांतिप्रिय आंदोलन को उग्र बनाने के लिए एक कार्यालय आदेश 10 जुलाई 2025 को जारी कर दिया कि विद्युत मुख्यालय और प्रदेश में विद्युत कार्यालय पर कर्मचारि, पेंशनर, अभियंता अपनी मांगों को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते । इस कार्यालय पत्र का हम पुरजोर विरोध करते हैं ।

ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत

प्रयागराज। मेजा थाना क्षेत्र के कोहड़ार गांव के समीप मंगलवार रात ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि मेजा थाना क्षेत्र के कोहड़ार गांव निवासी मोहम्मद लतीफ पुत्र मुनौवर अली की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई।

प्रसिद्ध स्पिरिचुअल कोच शैलजा सचदेवा को अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा एसबीआर 2025 अवॉर्ड से नवाजा गया

दिव्य दिल्ली : हाल ही में मुंबई में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में प्रसिद्ध हैप्पीनेस एंड माइंडसेट स्पिरिचुअल कोच, टैरो रीडर, रेकी मास्टर टीचर और न्यूमरोलॉजिस्ट शैलजा सचदेवा को प्रतिष्ठित रइफ 2025 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी के करकमलों से प्राप्त हुआ, जिसने इस पल को और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बना दिया। शैलजा सचदेवा की जीवन यात्रा एक गहरी प्रेरणा है एक समर्पित गृहिणी से एक सशक्त आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने तक का उनका सफर परिवर्तन, साहस और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उन्होंने न सिर्फ खुद को पहचाना, बल्कि अनेकों लोगों की ज़िंदगी को सकारात्मक दिशा दी। उनकी सेवाएं उन लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई हैं जो हीलिंग, उद्देश्य और आत्म-खोज के मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं। यह पुरस्कार उनके व्यक्तिगत प्रयासों की ही नहीं, बल्कि उस गहरे और व्यापक प्रभाव की भी मान्यता है, जो उन्होंने समाज और व्यक्तियों के जीवन पर डाला है। उनका कार्य प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, आधुनिक अंतर्दृष्टि और करुणा का सुंदर संगम है, जो लोगों को उनके सर्वोच्च आत्म से जोड़ने में मदद करता है। शैलजा के सत्र केवल जीवन की समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे अनुभव जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति, उद्देश्य और प्रकाश से जोड़ते हैं। यही कारण है कि वे आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी हैं। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सफलता का श्रेय शैलजा ईश्वरीय अनुकंपा, अपने गुरुओं जैसे कि Harpreet Kaur and Abhishek Madaan के आशीर्वाद और वर्षों की कठिन साधना को देती हैं। उनकी कहानी इस बात की सच्ची मिसाल है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और सेवा के पथ पर साहसपूर्वक चलता है, तो जीवन वास्तव में चमत्कारी रूप से बदल सकता है। अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो स्वयं नारीत्व, शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं, उनके हाथों यह सम्मान पाना शैलजा की यात्रा को एक गहरी प्रतीकात्मकता देता है।

सिविल अस्पताल के निकट सेवा केंद्र अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा-उपायुक्त

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

लोगों की सुविधा और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हुए, सिविल अस्पताल, पठानकोट के निकट स्थित सेवा केंद्र के कार्य समय में वृद्धि की गई है और अब यह सेवा केंद्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा, जबकि बाकी सेवा केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे।इस संबंध में जानकारी देते हुए, पठानकोट के उपायुक्त श्री आदित्य उप्पल ने बताया कि आम लोगों से सुझाव लेने और लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने काम या किसी अन्य कारण से दिन में सेवा केंद्र पर अपना काम करवाने में परेशानी हो रही थी, वे अब शाम को भी उक्त सेवा केंद्र पर पहुँचकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने कहा कि सेवा केंद्रों से सेवाएं लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397